उड़ान की कोई सीमा नहीं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना ही असली पहचान है: डॉ. स्वरलीन कौर

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 39 | मूल्य 05 रुपये | 15-21 फरवरी, 2026

उत्तराखंड में गुमशुदगी बनती जा रही है खतरनाक ट्रेंड

देहरादून में 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी' का सच

देहरादून का "सुकून लहूलुहान" 16 दिन में पांच हत्याएं

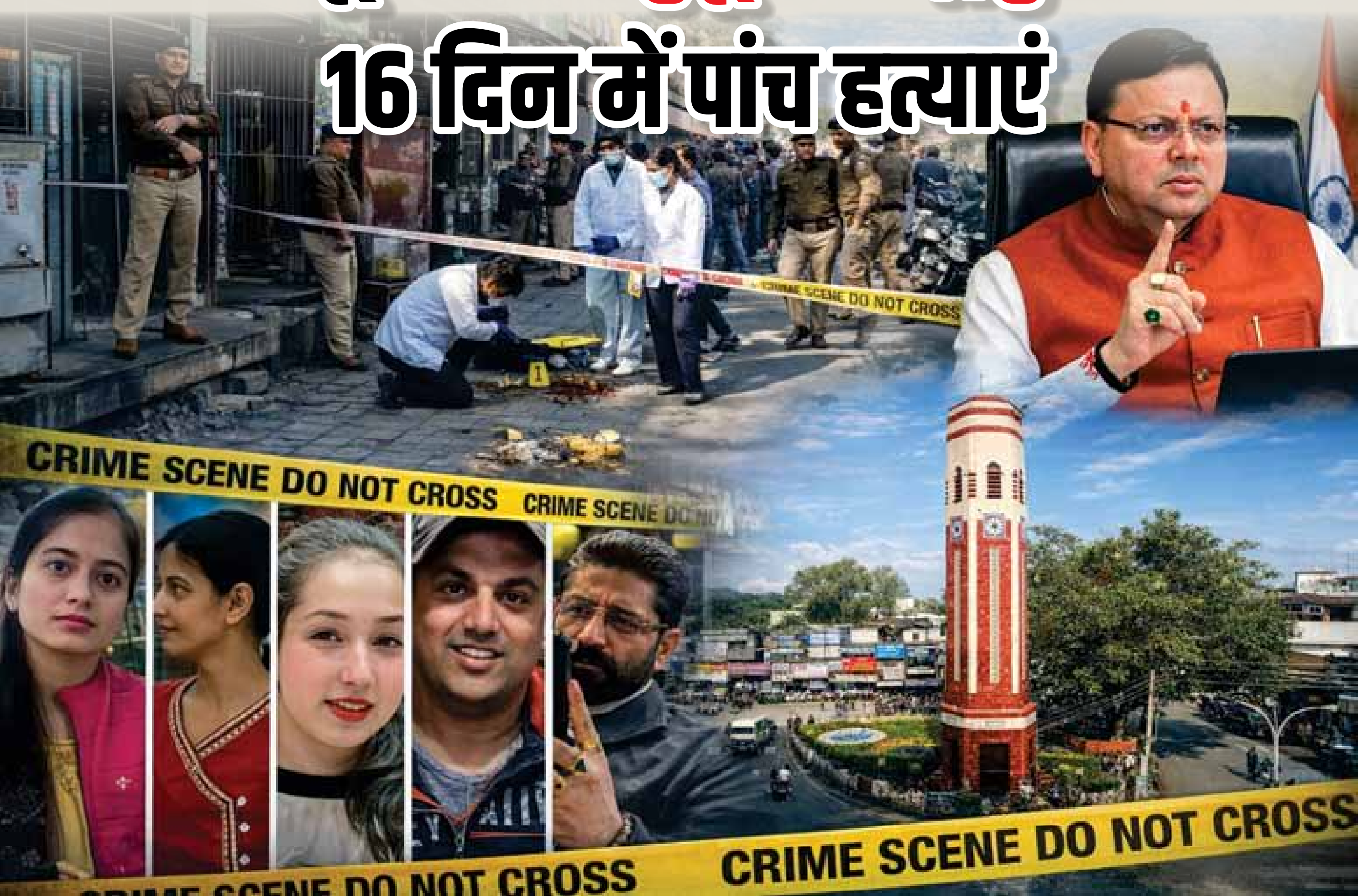

वर्ष 15 | अंक 39

दिव्य हिमगिरि

15-21 फरवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा आईशा प्रिंटिंग प्रेस, 292/1, चुक्खूवाला, ओंकार रोड, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

संपादकीय

एसआईआर: लोकतंत्र पर भरोसा करे राज्य सरकार

लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची में समय-समय पर संशोधन जरूरी है। इसी मकसद से देश के विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। मगर इसमें कई तरह की बाधाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कभी बड़ी संख्या में नागरिकों को मसविदा सूची से बाहर करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो कभी सियासी दलों की ओर से इस प्रक्रिया में नियमों के विपरीत दखल देने के आरोप लग रहे हैं। जाए, ताकि सभी पात्र नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित रह सके और अपात्र या मृतकों के नाम सूची से हटाने का कार्य बिना किसी विवाद या बाधा के पूरा हो सके। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल से जुड़े ऐसे ही एक मामले में सोमवार को सभी राज्यों को स्पष्ट कर दिया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न आशंकाओं का निरा करण करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत बिहार से हुई थी और तब से लेकर यह प्रक्रिया विवादों में है। शुरू में चुनाव आयोग की ओर से आधार कार्ड को पहचान पत्र के दस्तावेज में शामिल न करने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। आयोग का तर्क था कि आधार को नागरिकता का पहचान पत्र नहीं माना जा सकता, मगर बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसे पहचान के दस्तावेज में शामिल कर लिया गया। अब पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया पर आए दिन नए-नए सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने खुद राज्य में मसविदा सूची में छूट गए मतदाताओं की सुनवाई की प्रक्रिया रोकने का निर्देश दिया था। आयोग ने माना था कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में तकनीकी समस्या की वजह से कई लोगों के नाम मसविदा सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं और ऐसे लोगों के लिए फिलहाल व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं है। मगर यह बात भी उतनी ही अहम है कि आयोग की इस कवायद में किसी राज्य सरकार का सीधे तौर पर दबाव या दखल देना उचित नहीं हो सकता। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सफल तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों की भी इसमें अहम भूमिका है। इसके लिए पर्याप्त और सक्षम कर्मी उपलब्ध कराने का जिम्मा राज्य सरकार का होता है। ऐसे में अपेक्षा की जाती है कि इसमें सियासत को दूर रखकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग सहयोग एवं समन्वय के साथ काम करेंगे। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में कुछ और कर्मियों को पुनरीक्षण प्रक्रिया में तैनात करने की मांग करता रहा है, जिस पर राज्य सरकार अब जाकर राजी हुई है। अगर सरकार इस पर पहले ही हामी भर देती, तो इस कार्य में लगे अन्य कर्मियों को भी काम का दबाव नहीं झेलना पड़ता, जिसको लेकर राज्य में सत्तारूढ़ दल की ओर से ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। चुनाव आयोग की भी यह प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनी रहे।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

उत्तराखंड में गुमशुदगी बनती जा रही है खतरनाक ट्रेंड

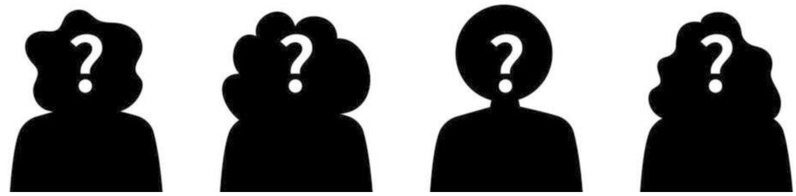

उत्तराखंड में बच्चों और महिलाओं की गुमशुदगी: एक खतरनाक ट्रेंड की चेतावनी

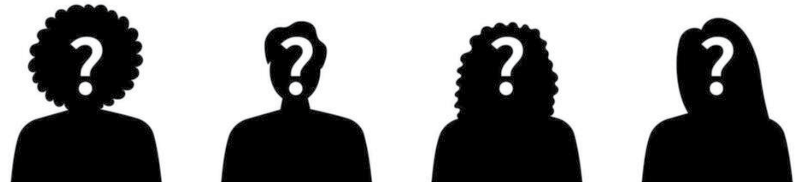

अनूप नौटियाल
सामाजिक कार्यकर्ता एवं विश्लेषक

उत्तराखंड जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले राज्य में बच्चों के साथ-साथ महिलाओं की गुमशुदगी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक ताने-बाने से जुड़ा बहुआयामी संकट है। 2023 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि इन घटनाओं को अलग-अलग मामलों के रूप में नहीं, बल्कि एक उभरते हुए खतरनाक ट्रेंड के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र या जिले में कम समय के भीतर लगातार गुमशुदगी की घटनाएँ सामने आती हैं, तो इसे संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी बड़े सामाजिक या आपराधिक संकेत की ओर इशारा कर सकता है। गुमशुदगी के पीछे सामाजिक असुरक्षा, आर्थिक विषमता, पलायन, डिजिटल जोखिम और मानव तस्करी जैसे कारण भूमिका निभा सकते है। अब समय आ गया है कि इन मामलों को समग्र और डेटा आधारित दृष्टिकोण से देखा जाए तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन गुमशुदगी के सभी मामलों को जोड़कर समग्र विश्लेषण कर रहा है? क्या महिलाओं और किशोरियों के मामलों को अलग से विश्लेषित किया जा रहा है? क्या डेटा-आधारित ट्रेंड स्टडी की जा रही है? क्योंकि छोटी अवधि में घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी संगठित या संरचनात्मक समस्या की ओर संकेत कर सकती है। आशंका यह भी है कि क्या इन गुमशुदगियों के पीछे मानव तस्करी का कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है? क्या कमजोर वर्ग, महिलाएं और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? क्या गुमशुदगी के मामलों की जांच में तस्करी के एंगल को गंभीरता से परखा जा रहा है? क्या अंतरराज्यीय गिरोहों की संभावित भूमिका की पड़ताल हो रही है?

यदि ऐसा कोई नेटवर्क सक्रिय है, तो यह केवल राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की चिंता का विषय हो सकता है।

उत्तराखंड जैसे अपेक्षाकृत छोटे और शांत माने जाने वाले राज्य में गुमशुदगी के मामलों में लगातार वृद्धि एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। इस स्थिति को राज्य के आकार और जनसंख्या के संदर्भ में गंभीरता से देखा जाना चाहिए। छोटे राज्यों में यदि गुमशुदगी का अनुपात अधिक हो, तो इसे सामान्य प्रवृत्ति मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में प्रारंभिक वर्ष में गुमशुदगी के 2437 मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर 4095 हो गये और वर्तमान में कुल गुमशुदगी के मामलों की संख्या 6532 तक पहुँच चुकी है। यह वृद्धि केवल सांख्यिकीय बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक तंत्र के लिए एक गंभीर संकेत है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या हजारों में दर्ज की गई है, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड में पिछले वर्षो के लंबित मामलों सहित गुमशुदा लोगों की संख्या 6,000 से अधिक तक पहुंच चुकी थी। इनमें से लगभग 38 प्रतिशत लोग बरामद किए गए, जबकि अब भी करीब 2280 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए यह संख्या असामान्य रूप से अधिक है ओर इन लंबित मामलों की संख्या प्रशासनिक दक्षता पर सवाल उठाती है तो रिकवरी रेट संतोषजनक नहीं माना जा सकता।

अन्य हिमालयी राज्यों से तुलना

यदि उत्तराखंड की तुलना अन्य हिमालयी राज्यों से की जाए, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है-

राज्य	कुल गुमशुदगी के मामले	बरामद
उत्तराखंड	6532	2701
हिमाचल प्रदेश	4176	1602
त्रिपुरा	2161	729
मेघालय	334	81
अरुणाचल प्रदेश	257	94

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में गुमशुदगी के मामलों की संख्या अधिक है।

विशेष रूप से मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह संख्या काफी कम है, जबकि उत्तराखंड में इसका स्तर चिंताजनक रूप से ऊँचा है।

यदि मामलों को अलग-अलग फाइलों में सीमित कर दिया जाए और व्यापक विश्लेषण न हो, तो बड़ी तस्वीर कभी सामने नहीं आ पाएगी।

''गुमशुदगी को केवल कानून-व्यवस्था के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं है। यह सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का भी विषय है।'' उन्होंने जोर दिया कि स्कूल स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम अभिभावकों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। लंबित मामलों की विशेष जांच (एसआईटी) का गठन, गुमशुदगी डेटा का सार्वजनिक ऑडिट, मानव तस्करी विरोधी इकाइयों को सशक्त करना।

पुलिस, सामाजिक संगठनों और मीडिया के बीच समन्वय, संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी और जागरूकता अभियान, बरामद बच्चों और महिलाओं के पुनर्वास व काउंसलिंग की व्यवस्था कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जो भविष्य में गुमशुदगी के मामलों में कमीं ला सकते हैं। क्योंकि देखने में यह भी आया है कि कई परिवार खासकर लड़कियों के मामलों में सामाजिक बदनामी के डर से तुरंत शिकायत दर्ज नहीं कराते। डेटा और जमीनी हकीकत में अंतर-कुछ मामलों में गुमशुदगी दर्ज नहीं होती, जिससे वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाती। बरामद बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और सामाजिक पुनर्वास की ठोस व्यवस्था का अभाव है। पुलिस और प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया गुमशुदगी के मामलों में ''गोल्डन ऑवर'' की रणनीति अपनाना जरूरी है। स्थानीय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए समितियाँ बनाई जा सकती हैं और इसके माध्यम से स्कूल और पंचायत स्तर पर निगरानी तंत्र विकसित किया जा सकता है। बच्चों और अभिभावकों दोनों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान बहुत ही आवश्यक हैं। बरामद बच्चों के मानसिक और सामाजिक काउंसिलिंग तथा पुनर्वास को प्राथमिकता देना होगा।

हमारे उत्तराखंड जैसे शांत और सुरक्षित माने जाने वाले राज्य में हजारों लोगों का लापता होना केवल आंकड़ा नहीं है, यह एक गंभीर सामाजिक और नीतिगत चुनौती है। गुमशुदगी की घटनाओं को अलग-अलग केस मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अब आवश्यकता है, समग्र जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही की। सवाल यह नहीं कि कितने लोग लापता हैं।

सवाल यह है–
क्यों? कैसे? और कब तक?

विधानसभा के बजट सत्र को न्यूनतम 21 दिवस एवं 3 सोमवारों सहित आहूत किया जाए

यशपाल आर्या
नेता प्रतिपक्ष
उत्तराखंड विधानसभा

लोकतंत्र में सरकार विधानसभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में प्रश्नकाल तथा अन्य संसदीय नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा पक्ष एवं विपक्ष के माननीय विधायकगण अपनी-अपनी विधानसभाओं तथा राज्य से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से उत्तर मांगते हैं। विधानसभा की कार्यसंचालन नियमावली में माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार सुनिश्चित किए गए हैं तथा संबंधित विभागों की ओर से तथ्यपूर्ण और संतोषजनक उत्तर देना संबंधित मंत्रियों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रत्येक मंत्री के अधीन विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्धारित दिवस तय होते हैं। चतुर्थ एवं पंचम विधानसभा की परंपरा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के प्रश्नों के लिए सोमवार का दिन नियत है।

वर्तमान पंचम विधानसभा (29 मार्च 2022 से प्रारंभ) के अब तक 9 सत्र आयोजित हुए हैं तथा कुल 32 उपवेशन (कार्य दिवस) हुए हैं। अन्य राज्यों की तुलना में यह संख्या अत्यंत कम है। इन 32 उपवेशनों में एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब प्रश्नकाल सहित सोमवार का दिन निर्धारित हुआ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन राज्य के लगभग 75 विभागों में से लगभग 40 विभाग हैं, जो कुल विभागों की आधी से अधिक संख्या है। इन विभागों में मंत्रिपरिषद, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, गृह, पेयजल, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, शहरी विकास एवं संसदीय कार्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग सम्मिलित हैं। प्रश्नकाल सहित सोमवार को विधानसभा न चलने के कारण राज्य की कानून-व्यवस्था, विभागीय भ्रष्टाचार, आपदा प्रबंधन की तैयारियों, ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति जैसे गंभीर विषयों पर सरकार से समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश सत्र केवल दो या तीन दिन चले, जिससे अन्य मंत्रियों के विभागों से संबंधित निर्धारित दिवस भी नहीं आ पाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी, शीघ्र ही राज्य का बजट सत्र आहूत होने जा रहा है। इस सत्र में आपके द्वारा वित्त मंत्री के रूप में बजट भाषण, सामान्य बजट पर चर्चा, विभागवार अनुदान मांगों पर विचार तथा वित्त विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न होने हैं। ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि विधानसभा का संचालन पर्याप्त अवधि तक हो, ताकि जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठा सकें और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि आगामी बजट सत्र को न्यूनतम 21 दिवसों के लिए तथा कम से कम 3 सोमवारों सहित आहूत किया जाए, ताकि प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय हो सके और राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया सशक्त हो।

देहरादून में 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी' का अफवाह: जांच में निकली सच्चाई

डॉ. मोहन भुलानी
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले कुछ दिनों से 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी' के नाम पर फैलाए गए भ्रम ने सियासी और सोशल मीडिया पर तूफान मचा रखा था। इस मुद्दे को जनसांख्यिकीय परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेंज) से जोड़कर पेश किया गया और इसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए) की सुरक्षा के लिए खतरा बताकर राष्ट्रभक्ति का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब इस मामले की गहन जांच हुई, तो सच्चाई पूरी तरह से अलग निकली, जो अफवाह फैलाने वालों के एजेंडे की पोल खोलती है।

कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, सिर्फ भ्रम

विवादित जमीन पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मदरसा या मस्जिद बनने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। दावा किया जा रहा था कि इलाके में मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है, जिससे स्थानीय जनसांख्यिकी बदल रही है। हालांकि, स्थानीय प्रशासन और स्वतंत्र जांचकर्ताओं की पड़ताल में कोई ऐसी संरचना नहीं मिली। उल्टा, जमीन के अधिकांश प्लॉट हिंदू समुदाय के लोगों के नाम पर पाए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार, विवादित क्षेत्र में कुल प्लॉटों में से 70% से अधिक हिंदू परिवारों के हैं। ये लोग स्थानीय निवासी हैं, जिन्होंने घर बनाने या निवेश के लिए जमीन खरीदी थी।

मध्यमवर्गीय परिवारों की मेहनत दांव पर

कई परिवारों ने अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर छोटे-छोटे प्लॉट खरीदे थे। अफवाहों के कारण इनकी संपत्ति पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन जांच ने उन्हें राहत दी। अफवाह फैलाने वालों ने 'मुस्लिम यूनिवर्सिटी' का हल्ला बोलकर दावा किया कि 'बाहरी लोग' ने इलाके पर कब्जा कर लिया है। लेकिन दस्तावेजों से पता चला कि ज्यादातर खरीदार स्थानीय हिंदू ही हैं, जो दशकों से यहां रहते हैं।

आईएमए की सुरक्षा से जोड़कर सियासत

इस मुद्दे को और तूल देने के लिए इसे आईएमए की सुरक्षा से जोड़ा गया। आईएमए देश की प्रमुख सैन्य संस्था है, और इसका नाम लेकर मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि संवेदनशील संस्थानों का हवाला देकर ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही थी। एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'यह सब वोट बैंक की राजनीति है। असली मुद्दा विकास का है, न कि समुदाय का।'

दस्तावेजों ने खोली पोल

जब दस्तावेजों की जांच की गई, तो पता चला कि शोर मचाने वाले और जमीन खरीदने वाले दोनों ही पक्ष हैरान थे। जिन्हें 'बाहरी' और 'खास समुदाय' का बताया जा रहा था, वे असल में स्थानीय हिंदू निकले जिन्होंने घर बनाने के लिए जमीन ली थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई अवैध निर्माण या कब्जा नहीं हुआ है, और सभी लेन-देन वैध हैं। स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई तस्वीरें और वीडियो पुरानी या असंबंधित थीं, जिन्हें गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया गया। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। साइबर सेल इस मामले की जांच कर रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी अफवाहों पर रोक लग सके। स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है और मांग की है कि विकास पर ध्यान दिया जाए, न कि विभाजनकारी मुद्दों पर।

धौलास भूमि विवाद में भूखंड धारकों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 'मुस्लिम कॉलोनी' की खबरों को बताया निराधार

देहरादून। जनपद के मौजा धौलास स्थित एक भूमि (खाता संख्या 531) को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार चैनलों पर चल रही खबरों के खिलाफ अब भूखंड खरीदार लामबंद हो गए हैं। 'शेखुल हिन्द एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट' से जुड़े इस मामले में खरीदारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा है और चल रही खबरों को भ्रामक व दुर्भावनापूर्ण करार दिया है।

खबरों का खंडन: 'सभी खरीदार हिंदू और पूर्व सैनिक'

ज्ञापन में भूखंड धारकों ने स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि पर किसी 'विशेष समुदाय' की बस्ती बसाने या क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने की खबरें पूरी तरह झूठ हैं।

खरीदारों ने निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं:

हिंदू खरीदार: उक्त भूमि पर लगभग 165 व्यक्तियों ने अपने जीवन भर की कमाई निवेश कर भूखंड खरीदे हैं, और ये सभी हिंदू समुदाय से हैं।

पूर्व सैनिकों की भागीदारी: खरीदारों में बड़ी संख्या उत्तराखंड के मूल निवासियों और उन पूर्व सैनिकों की है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया है।

महादेव रेजीडेंसी: सभी 165 खरीदारों ने मिलकर इस स्थान को 'महादेव रेजीडेंसी' के नाम से सीमांकित किया है। भूखंड धारकों का कहना है कि उन्होंने भूमि खरीदने से पहले स्थानीय राजस्व अधिकारियों (परगनाधिकारी, तहसीलदार व लेखपाल) से पूरी जानकारी जुटाई थी। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में 'संक्रमणीय भूमिधर श्रेणी 1-क' के तहत दर्ज थी और सभी प्रकार के विवादों से मुक्त थी। खरीद के समय नियमानुसार स्टाम्प शुल्क चुकाया गया है और वर्तमान में इस पर कोई आवासीय निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। वन विभाग और राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी प्राप्त है।

ब्लैकमेलिंग और साजिश का आरोप

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानीय लोग 'भयादोहन' (Extortion) और निजी स्वार्थ के चलते मीडिया में गलत खबरें फैला रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि ऐसी भ्रामक खबरों के कारण उनकी जमा-पूंजी खतरे में पड़ गई है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। भूखंड धारकों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि यदि इस भूमि के संदर्भ में सरकार द्वारा कोई भी जांच या कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, तो एकपक्षीय कार्रवाई से पूर्व उनका पक्ष भी सुना जाए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए, अन्यथा उनके साथ घोर अन्याय होगा।

उत्तराखंड में दायित्वधारियों की नई सूची जल्द!

देवभूमि की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड शासन द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित आयोगों, निगमों, परिषदों, समितियों और संस्थानों में तैनात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और सदस्यों का विस्तृत ब्योरा तलब किए जाने के बाद यह लगभग स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि दायित्वधारियों की नई सूची पर मंथन अंतिम चरण में है। शासन का यह शासकीय आदेश महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे संभावित पुनर्गठन की ठोस तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। कई पदों पर लंबे समय से लंबित नियुक्तियों, निष्क्रिय दायित्वों और राजनीतिक संतुलन के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यापक समीक्षा कर रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के भीतर भी दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है, जबकि संगठन और सरकार के बीच समन्वय बैठकों का दौर तेज होने की चर्चा है। देवभूमि की राजनीति में लंबे समय से प्रतीक्षित इस सूची को लेकर कार्यकर्ताओं और दावेदारों में उत्सुकता चरम पर है। शासन के ताजा कदम ने संकेत दे दिए हैं कि प्रतीक्षा की घड़ी अब अधिक लंबी नहीं हो सकती और नई सूची जारी होते ही सत्ता और संगठन दोनों में नई सियासी सरगर्मी देखने को मिल सकती है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

देवभूमि की सियासत में लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। उत्तराखंड शासन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण शासकीय आदेश जारी कर विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित आयोगों, निगमों, परिषदों, समितियों और स्वायत्तशासी संस्थानों में तैनात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकारों और सदस्यों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। इस औपचारिक लेकिन बेहद अहम कदम ने संकेत दे दिए हैं कि दायित्वधारियों की नई सूची पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है और सूची जारी होने में अब अधिक समय नहीं लग सकता। शासन स्तर से मांगी गई जानकारी में न केवल वर्तमान में कार्यरत पदाधिकारियों का विवरण, बल्कि रिक्त पदों, कार्यकाल की स्थिति, नियुक्ति की तिथि और दायित्वों की प्रकृति से संबंधित सूचनाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि यह महज आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि व्यापक समीक्षा की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस कदम को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में दायित्वधारियों की सूची का विशेष महत्व रहा है। सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने, वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक जिम्मेदारी देने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का यह प्रमुख माध्यम माना जाता है। कई आयोग और निगम लंबे समय से आंशिक रूप से निष्क्रिय स्थिति में हैं या वहां नियमित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में शासन की यह पहल इन संस्थाओं को सक्रिय करने की दिशा में भी कदम मानी जा रही है। देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजनीतिक हलकों में इस समय एक ही चर्चा है, "सूची कब जारी होगी?" सत्तारूढ़ दल के भीतर कई वरिष्ठ और युवा नेता लंबे समय से दायित्व मिलने की प्रतीक्षा में हैं। संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि उन्हें अवसर मिल सकता है। सरकार इस बार क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक सक्रियता जैसे कारकों को ध्यान में रखकर सूची तैयार कर रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि नई सूची केवल औपचारिक नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से तैयार की जा रही है। शासन द्वारा मांगी गई जानकारी में यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि किन आयोगों और निगमों में कितने पद रिक्त हैं। कई संस्थाओं में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद महीनों से खाली है, जिससे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। यदि इन संस्थाओं में नियमित नियुक्तियां हो जाती हैं तो नीतिगत फैसलों में तेजी आएगी और विभागीय कार्यों में भी गति देखने को मिलेगी विपक्षी दल भी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार को पारदर्शिता बरतते हुए नियुक्तियां करनी चाहिए और राजनीतिक समीकरण ों के बजाय योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि सत्तारूढ़ दल का दावा है कि नियुक्तियां पूरी तरह नियमों के तहत और शासनादेशों के अनुरूप की जाएंगी। हालांकि शासन की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तेजी से विभागों से जानकारी मांगी गई है, उससे यह संकेत मिलते हैं कि प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच रही है। इस तरह की जानकारी संकलन के बाद अल्प समय में निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक हलकों में अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सप्ताह प्रदेश की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकते हैं। शासन के ताजा आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार दायित्वों की संरचना को लेकर गंभीर है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अंतिम सूची में किन नामों को स्थान मिलता है और किन चेहरों को प्रतीक्षा जारी रखनी पड़ती है। देवभूमि की सियासत में आने वाले दिन नई राजनीतिक हलचल लेकर आ सकते हैं।

शासन की कवायद से तेज हुई सियासी अटकलें

उत्तराखंड में दायित्वधारियों की संभावित नई सूची को लेकर चर्चाएं और तेज हैं। शासन ने सभी संबंधित विभागों से वर्तमान पदाधिकारियों का विवरण, रिक्त पदों की स्थिति और कार्यकाल संबंधी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक बताया जा रहा है, क्योंकि कई संस्थाओं में लंबे समय से नियुक्तियां लंबित हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश की सत्ता संरचना में दायित्वधारियों की भूमिका केवल औपचारिक नहीं होती, बल्कि वे सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। ऐसे में नियुक्तियों के माध्यम से सरकार संगठनात्मक संतुलन साधने का प्रयास करती है। इस बार सूची में नए और सक्रिय चेहरों को स्थान मिलने की संभावना अधिक है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि जो कार्यकर्ता और नेता संगठनात्मक रूप से सक्रिय हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है, लेकिन शासन के ताजा आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सूची कब जारी होगी और किन नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि शासन की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जिस तेजी से विभागों से जानकारी मांगी गई है, उससे यह संकेत मिलते हैं कि प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच रही है। आमतौर पर इस तरह की जानकारी संकलन के बाद अल्प समय में निर्णय लिया जाता है।

उड़ान की कोई सीमा नहीं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना ही असली पहचान है: डॉ. स्वरलीन कौर

यक्तित्व विकास, नेतृत्व और आत्मविश्वास की प्रखर प्रशिक्षक डॉ. स्वरलीन कौर से पूनम आर्य की विशेष बातचीत

अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शिक्षा के बारे में बताइए।

मैं एक ऐसे संस्कारवान और आत्मगौरव से परिपूर्ण परिवार में पली-बढ़ी हूँ, जहाँ बेटियों का स्वागत लक्ष्मी के समान किया जाता है। परिवार में मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरी दो छोटी बहनें हैं। मेरी माता एक समर्पित गृहिण ी हैं, जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ हमारा पालन-पोषण किया और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमें केवल अच्छे संस्कार ही नहीं दिए, बल्कि हमारे स्वभाव और सोच की बारीकियों को भी संवारा। मेरे पिता एक व्यवसायी हैं। उन्होंने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हमारा आध्यात्मिक और नैतिक विकास समान रूप से हो। हमारे पालन-पोषण में मानसिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक- इन सभी आयामों पर विशेष बल दिया गया। बचपन से ही हमारे जीवन में एक मूल मंत्र रोपा गया- "उड़ान भरो, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है; लेकिन सहानुभूति, करुणा और विचारशीलता को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाए रखना।" आज भी यही मूल्य मेरे व्यक्तित्व और निर्णयों का आधार हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यमुनानगर स्थित संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल से हुई। मैंने अंग्रेजी विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। शैक्षणिक शिक्षा के साथ-साथ मैंने सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्ट्रेटेजीज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त किए, ताकि मैं स्वयं को केवल अकादमिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और नेतृत्व क्षमता के स्तर पर भी निरंतर विकसित कर सकूँ।

अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा क्या रही?

मेरा प्रोफेशन मेरे लिए केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि मेरे जीवन-उद्देश्य का स्वाभाविक विस्तार है। यह कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि अनुभवों की निरंतर यात्रा का परिणाम था। अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करते समय मैंने शब्दों की शक्ति को गहराई से महसूस किया। मुझे समझ आया कि शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते वे आत्मविश्वास जगा सकते हैं, टूटे मन को संबल दे सकते हैं और किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यहीं से मेरे भीतर यह स्पष्ट हुआ कि मैं केवल पढ़ाना नहीं चाहती, बल्कि लोगों को अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और पहचान देना चाहती हूँ। करियर के शुरुआती वर्षों में जब मैंने युवाओं, विद्यार्थियों और पेशेवरों के साथ काम करना शुरू किया, तो एक बात बार-बार सामने आई, बहुत से लोग सक्षम होते हुए भी आत्मविश्वास की कमी के कारण स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाते। कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। यही अनुभव मेरे लिए निर्णायक मोड़ बना। मैंने पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स को केवल एक विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में अपनाया। मेरा उद्देश्य है लोगों को यह एहसास कराना कि उनकी आवाज मायने रखती है और उनका व्यक्तित्व उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा वे क्षण हैं जब कोई मंच से डरने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है, जब किसी छात्र की आँखों में चमक दिखती है, या किसी युवा में नेतृत्व की चेतना जागती है। यही मेरे लिए सच्ची सफलता है।

आपकी प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रही हैं?

यदि मैं अपनी उपलब्धियों की बात करूँ, तो कुछ सम्मान मेरे लिए केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि मेरे कार्य की आत्मिक स्वीकृति हैं। वर्ष 2023 में मुझे पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया। यह मेरे जीवन का अत्यंत विनम्र कर देने वाला क्षण था। यह नामांकन इस बात का प्रमाण था कि निष्ठा और उद्देश्य के साथ किया गया कार्य समाज और व्यवस्था दोनों की दृष्टि में अपना स्थान बना सकता है। मुझे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्व ारा भी सम्मानित किया गया, जिससे मेरे कार्य को वैश्विक पहचान मिली। यूरोपियन एशियन मैगजीन के कवर पेज पर स्थान मिलना मेरे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक, मेरे कार्य की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक रहा। अपने गृह राज्य से प्राप्त "उत्तराखंडी रत्न" पुरस्कार मेरे लिए विशेष भावनात्मक महत्व रखता है। महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा सामाजिक और शैक्षणि क योगदान के लिए मिला सम्मान भी मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हालाँकि, यदि सच कहूँ तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि आज भी वही है, जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है, "आपकी वजह से मैं खुद पर विश्वास कर पाया/पाई।" यही मेरे लिए किसी भी पुरस्कार से बड़ा सम्मान है।

आपकी भविष्य की योजनाएँ क्या हैं?

मेरी भविष्य की योजनाएँ किसी व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं हैं। मेरा लक्ष्य एक स्थायी और संरचित प्रभाव का निर्माण करना है, जो व्यक्ति, संस्था और समाज-तीनों स्तरों पर दिखाई दे। मैं शिक्षा और व्यक्तित्व विकास को अधिक संस्थागत और सुलभ बनाना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य ऐसे मॉडल

विकसित करना है, जिनके माध्यम से संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों को औपचारिक शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए। मैं अपने अनुभवों को पुस्तकों, पाठयक्रमों और नीति-स्तरीय सुझावों के रूप में संकलित करना चाहती हूँ, ताकि व्यक्तित्व विकास केवल प्रेरणात्मक भाषण ों तक सीमित न रहे, बल्कि एक मापनीय और प्रभावशाली अनुशासन के रूप में स्थापित हो। इसके साथ ही, मेरा लक्ष्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुँचना है, जहाँ प्रतिभा तो है, लेकिन मंच और मार्गदर्शन की कमी है। दीर्घकालिक रूप से मैं अपने कार्य को नीति-निर्माण और शैक्षणिक सुधार के स्तर तक ले जाना चाहती हूँ।

यदि इसे एक वाक्य में कहूँ- मैं ऐसे व्यक्तित्वों के निर्माण की दिशा में कार्य करना चाहती हूँ जो केवल सफल ही नहीं, बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार और समाजोपयोगी भी हों।

दिव्य हिमगिरि के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी?

मैं आपकी प्रतिष्ठित पत्रिका दिव्य हिमगिरि के माध्यम से युवाओं और महिलाओं से कहना चाहूँगी, परिस्थितियाँ आपकी पहचान तय नहीं करतीं, आपका दृष्टिकोण करता है। आज जानकारी की कोई कमी नहीं, लेकिन आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट दिखाई देती है। लोग स्वयं की तुलना दूसरों से करते हुए अपनी क्षमता को कम आँकने लगते हैं। मेरा संदेश है- अपने भीतर झाँकना सीखिए, क्योंकि वास्तविक शक्ति वहीं से जन्म लेती है। सफलता केवल पद, प्रसिद्धि या पुरस्कार नहीं है। सच्ची सफलता वह है, जब आप अपने मूल्यों से समझौता किए बिना आगे बढ़ें और अपनी प्रगति के साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएँ। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहूँगी- असफलताओं से डरिए मत, वे आपकी तैयारी का हिस्सा हैं। और महिलाओं से- अपनी आवाज को दबाइए मत। आपकी सोच और आपका अस्तित्व महत्त्वपूर्ण है।

यदि अपनी बात को एक पंक्ति में समेटूँ तो-

उड़ान भरिए, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं है; लेकिन जमीन से जुड़े रहिए, क्योंकि वहीं से आपकी पहचान बनती है।

उत्तरायणी कौथिक मंच से सीएम धामी का आत्मनिर्भर उत्तराखंड संकल्प

देवभूमि की पावन वादियों में जब लोकधुनों की गूंज, पारंपरिक वेशभूषा की आभा और आस्था की उजास एक साथ मिलती है, तब उत्तरायणी कौथिक केवल उत्सव नहीं, बल्कि जनभावनाओं का महासंगम बन जाता है। देहरादून के परेड ग्राउंड में सजे इस सांस्कृतिक पर्व के मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड का संकल्प दोहराते हुए विकास और संस्कृति को एक ही धारा के दो प्रवाह बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी लोक परंपराओं, भाषाओं, वाद्यों, नृत्यों और पर्वों से है, और इन्हीं जड़ों से शक्ति लेकर राज्य आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' की भावना को आत्मसात करते हुए स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, मिलेट्स, कुटीर उद्योगों और होम स्टे जैसी योजनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोक कलाकारों के संरक्षण, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और पहाड़ के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

जब देवभूमि की पावन वादियों में भक्ति, परंपरा और लोकधारा का संगम होता है, तब केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा को स्पर्श करने वाला आध्यात्मिक उत्सव जन्म लेता है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित चार दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव भी कुछ ऐसा ही दिव्य अनुभव बनकर उभरा, जहां लोक संस्कृति की रंगत, आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक सरोकार एक साथ स्पंदित होते नजर आए। देवभूमि उत्तराखंड की लोक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति बने उत्तरायणी कौथिक महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित चार दिवसीय इस महोत्सव में उन्होंने लोक कलाकारों, साहित्यकारों, कला-प्रेमियों और बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने का सशक्त माध्यम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरायणी कौथिक केवल उत्सव नहीं, बल्कि लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का व्यापक अभियान है। उन्होंने सेवा संकल्प फाउंडेशन और इसकी संस्थापक

गीता धामी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा राज्य की समृद्ध लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक कलाएं, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कारीगरी हमारी पहचान हैं और इन्हें संरक्षित करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने जागर, बेड़ा, मांगल, खुदेड़, छोपाटी जैसे लोकगीतों तथा छोलिया, पांडव और झोड़ा-छपेली जैसे लोकनृत्यों को उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा बताते हुए कहा कि इन्हें सहेजना और आगे बढ़ाना समय की मांग है। चार दिवसीय आयोजन में लगे स्टॉलों के माध्यम से पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और उत्तराखंडी व्यंजनों के प्रदर्शन की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'वोकल फॉर लोकल', 'मेक इन इंडिया', 'मेड इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा 'एक जनपद, दो उत्पाद' योजना और 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, कीवी मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। किसानों की आय बढ़ाने में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी राज्य अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को 'अचीवर्स' और स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर्स' श्रेणी प्राप्त हुई है। सिंगल विंडो सिस्टम को 'टॉप अचीवर्स' श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। खनन तत्परता सूचकांक में श्रेणी-सी में देश में दूसरा स्थान तथा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में अचीवर्स श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्डलाइफ और बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

उत्तरायणी कौथिक में 10 विशिष्टजनों को किया गया सम्मानित

महोत्सव के दौरान राज्यपाल द्वारा समाज सेवा, शिक्षा, कृषि, लोकसंस्कृति एवं खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 विशिष्टजनों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रेम प्रकाश बेलवाल (नैनीताल), कामिनी कश्यप, मनोरमा जोशी (अल्मोड़ा), भवान सिंह कोरंगा, प्रेमा रावत (बागेश्वर), कृष्णा (उत्तरकाशी), श्याम चन्द्र टम्टा (पौड़ी), कल सिंह राणा, ब्रिगेडियर दिनेश कुमार (देहरादून), मनोरमा जोशी (अल्मोड़ा) शामिल रहे। कार्यक्रम में गुरमीत कौर, सुबोध उनियाल, सौरभ थपलियाल, बीना भट्ट, गीता खन्ना, लेफ्टिनेंट जनरल नगेन्द्र सिंह, आरके जैन, पुनीत मित्तल, गीता रावत, कुसुम कंडवाल, विनोद उनियाल, विश्वास डाबर, श्याम अग्रवाल, शादाब शम्स, देवेंद्र भसीन, सुरेखा डंगवाल, एडवोकेट ललित जोशी, मुकेश कुमार, बलवीर उनियाल, गीताराम गौड़ सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे।

राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में जाखोल, हर्षिल, गुंजी और सूपी गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में राज्य को 'वन टू वॉच' पुरस्कार मिला है। वर्ष 2024 में मत्स्य विकास के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तथा हैदराबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में 'बेस्ट स्टेट फॉर प्रोमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम' सम्मान प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक कलाकारों के संरक्षण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। कोरोना काल में लगभग 3,200 सत्यापित कलाकारों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी गई। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं अस्वस्थ लोक कलाकारों को पेंशन प्रदान की जा रही है तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। लोक सांस्कृतिक लिपियों के प्रकाशन, आर्ट गैलरियों की स्थापना और साहित्यकारों को सम्मान एवं अनुदान प्रदान करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। गीता धामी ने कहा कि चार दिनों तक चले इस महोत्सव के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक उत्पादों और जीवनशैली को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल संस्था का नहीं बल्कि पूरे राज्य का उत्सव है। युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना और आधुनिकता के साथ संस्कृति का संरक्षण करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की अधिक से अधिक खरीदारी कर राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का आहवान किया। कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी, सतपाल महाराज, प्रसून जोशी, कल्पना सैनी, खजान दास, दुर्गेश्वर लाल, अनिल नौटियाल, भोपाल राम टम्टा, सुरेश गढ़िया, सुरेश चौहान, अजेय कुमार, बिशना देवी, अपर्णा जोशी, दीपम सेठ, हेमराज बजरंगी, मधु भट्ट, गीता खन्ना, गीताराम गौड़, विश्वास डाबर, श्याम अग्रवाल, विनोद उनियाल, नेहा शर्मा, हरक सिंह, मुकेश कुमार, ज्योति गैरोला सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संकल्प और सेवा का दिया संदेश

देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना, लोक परंपराओं और सामाजिक समरसता का जीवंत उत्सव बने उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 में परेड ग्राउंड, देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल) ने प्रतिभाग किया। "संस्कृति से समृद्धि की ओर" थीम पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया और सेवा संकल्प फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि सेवा संकल्प फाउंडेशन निरंतर संकल्प के साथ जनसेवा को आगे बढ़ा रहा है। संस्था का मूल भाव ही सेवा है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि जीवन में संकल्प ही व्यक्ति और समाज को दिशा देता है। यदि हम अपनी संस्कृति, परंपरा और धरोहर पर गर्व करने का संकल्प लें, तो समाज स्वतः सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि गीता धामी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में संस्था के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं, जो सराहनीय पहल है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तरायणी पर्व भारतीय संस्कृति में नवचेतना, सकारात्मक ऊर्जा और सामूहिकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति तभी जीवंत रहती

महोत्सव मन और आत्मा को जोड़ने वाला आध्यात्मिक उत्सवः स्वामी अवधेशानन्द गिरि

देवभूमि की वादियों में जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि चेतना का एक नया अध्याय भी प्रारंभ होता है। उत्तराखंड की पावन धरती पर पर्व और मेले केवल उत्सव नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का उत्सव हैं। यहां लोकगीतों में इतिहास सांस लेता है, वाद्य यंत्रों की थाप में परंपरा धड़कती है और सामूहिक आयोजन में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। उत्तरायणी का पर्व इसी सनातन सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जो मनुष्य को अपनी जड़ों, अपनी मिट्टी और अपनी आत्मा से जोड़ता है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित चार दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव ने इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप दिया। पूरा परिसर लोकधुनों, पारंपरिक वेशभूषा और उत्साह से सराबोर दिखाई दिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वामी अवधेशानन्द गिरि ने कहा कि उत्तरायणी कौथिक महोत्सव केवल लोक संस्कृति का उत्सव नहीं, बल्कि मन और आत्मा को जोड़ने वाला अनुभव है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में स्नेह, सहयोग और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार करते हैं। उत्तराखंड को संस्कृत की जननी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस देवभूमि में हर साधु-संत ने तपस्या की है और भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस राज्य का ऋणी है। उन्होंने आहवान किया कि उत्तरायणी महोत्सव को देश के अन्य हिस्सों तक भी ले जाया जाए, ताकि उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति जन-जन तक पहुंचे। सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी श्रीमती गीता धामी ने कहा कि यह महोत्सव आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को सशक्त मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति, किसान और स्वयं सहायता समूहों को अपने पारंपरिक उत्पादों और व्यंजनों को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत नशे के विरुद्ध जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया गया। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट ने कहा कि यह आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इसे युवाओं को सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाला मंच बताया।

है जब उसे सेवा, समर्पण और समाज के सहयोग से जोड़ा जाए। गीता धामी ने कहा कि परंपरागत रूप से उत्तरायणी पर्व राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता रहा है, लेकिन देहरादून में इस महोत्सव ने नई ऊर्जा का संचार किया है। लोग पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और यह आयोजन अब एक जीवंत सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि उत्तरायण ी कौथिक केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारी जीवंत परंपरा का प्रतीक बन गया है। उन्होंने बताया कि महोत्सव में उत्तराखंड के सभी जिलों से स्वयं सहायता समूह शामिल हुए हैं। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाजार मिला है और प्रदर्शनी में प्रस्तुत सामग्री उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। साथ ही प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां लोक संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। गीता धामी ने कहा कि ऐसे महोत्सव हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक चेतना का संदेश देते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने और भारत के विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

लोकधुनों की गूंज में झूमा परेड ग्राउंड

सांस्कृतिक संध्या में पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के जागर गीतों ने समां बांध दिया। लोकगायक फौजी ललित मोहन, सौरभ मैठाणी, बी.के. सामंत और राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। "मै पहाड़ो कु रैबासी" और "तू ऐजा ओ पहाड़" जैसे गीतों पर लोग देर तक थिरकते रहे। श्वेता माहरा की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा। पूरा मैदान तालियों और लोकधुनों की गूंज से जीवंत हो उठा।

प्रतिभाओं का सम्मान और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति

महोत्सव के अंतर्गत चित्रकला, भजन और पारंपरिक व्यंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में अंशिक चौहान ने प्रथम, कविशमा राय ने द्वितीय और अवनी सारियल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। व्यंजन प्रतियोगिता में अंकिता महर प्रथम, गुरुविंदर कौर द्वितीय और जमुना रावत तृतीय स्थान पर रहीं। इसके अतिरिक्त सुलोचना नेगी, देवकला, भूपाल सिंह नेगी, शैली बंसल और निधि थापा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण, विधायक सविता कपूर, दायित्वधारी राज्य मंत्री हेमराज बजरंगी, मधु भट्ट, डॉ. गीता खन्ना, गीताराम गौड़, स्वराज विद्वान, नेहा जोशी, विनोद उनियाल, निर्मला जोशी, मुन्नी भट्ट, आरुषि निशंक, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि भट्ट, ललित जोशी, नेहा शर्मा, बलदेव भट्ट सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। चार दिवसीय उत्तरायण ी कौथिक महोत्सव ने यह संदेश दिया कि लोक संस्कृति केवल परंपरा नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली शक्ति है, जो मन को आनंद, आत्मा को शांति और समाज को एकता का सूत्र प्रदान करती है।

निशंक ने सराहा सेवा संकल्प का कार्य, गीता धामी ने दिया 'लोकल से आत्मनिर्भर' का मंत्र

परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित चार दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 के दूसरे दिन यही दृश्य साकार हुआ। लोकगीतों की मधुर गूंज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप, हस्तशिल्प से सजे स्टॉल और आत्मनिर्भरता का संदेश, इन सबने मिलकर इस आयोजन को लोक संस्कृति का महाकुंभ बना दिया। दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेवा संकल्प फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था समाज के कमजोर वर्गों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य,

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में फाउंडेशन के योगदान को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और युवाओं को भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा संकल्प फाउंडेशन स्थानीय उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध करा रहा है और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी श्रीमती गीता धामी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तरायणी कौथिक महोत्सव देवभूमि की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक आस्थाओं और लोकगीतों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है और हमारे गीत-संगीत में हमारी आत्मा बसती है। बेड़ा गीत, मांगल गीत, चौती गीत जैसे पारंपरिक गीत ढोल, दमाऊ, ढोलकी, भंकोरा और रणसिंहा जैसे वाद्य यंत्रों की धुनों पर आज भी जीवंत हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी व्यंजन, मडुए की रोटी, झंगोरे की खीर, भट्ट की चुड़कानी और गहत की दाल, सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति-अनुकूल जीवनशैली का संदेश भी हैं। महोत्सव में 172 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 100 से अधिक निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। विभिन्न जिलों से आए काश्तकारों, शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच दिया गया है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प, बुनाई और रिंगाल उत्पादों के संरक्षण में मातृशक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये उत्पाद अब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान बना रहे हैं। श्रीमती धामी ने सभी से स्थानीय उत्पादों के अधिक उपयोग का आहवान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में सहभागी बनने की अपील की।

ऐपण प्रतियोगिता बनी आकर्षण का केंद्र

लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित ऐपण प्रतियोगिता ने विशेष आकर्षण बटोरा। प्रतिभागियों ने लकड़ी के तख्तों पर लाल पृष्ठभूमि में सफेद रंग से पारंपरिक ऐपण कला का सुंदर प्रदर्शन किया। बालिकाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस प्रतियोगिता को और भी विशेष बना दिया। नई पीढ़ी तक पारंपरिक कला पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय रहा। वहीं महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों पर भी जोर दिया गया। विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली और समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। रैली के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जन-जन को जागरूक किया गया।

गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी की प्रस्तुति ने बांधा समां

स्टार नाइट में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने लोकगीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ पद्मश्री बसंती बिष्ट, गोविंद, खुशी जोशी और ललित गित्यार की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। लोकधुनों पर झूमते दर्शकों ने देवभूमि की सांस्कृतिक आत्मा को सजीव होते देखा। महोत्सव के दूसरे दिन मां बाराही सांस्कृतिक दल, बुरांस कला केन्द्र के गोर्खाली ग्रुप, ब्रह्मकमल सांस्कृतिक दल गढ़वाल, नवोदय पर्वतीय कला केन्द्र दल तथा एस.जी. आर.आर स्कूल के बच्चों द्वारा वंदना सहित विभिन्न प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, विनय रुहेला, लीलावती राणा, गीताराम गौड़, रश्मि बर्द्धन, विदुषी, नेहा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उत्तरायणी कौथिक महोत्सव का दूसरा दिन यह संदेश देकर गया कि लोक संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की शक्ति और भविष्य की प्रेरणा है, जो समाज को जोड़ती है, आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाती है और देवभूमि की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है।

देहरादून का "सुकून लहूलुहान" 16 दिन में पांच हत्याएं

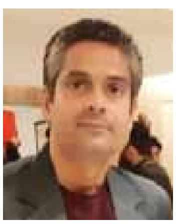

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

देवभूमि की राजधानी देहरादून इन दिनों ऐसी घटनाओं का गवाह बन रही है, जिन्होंने कानून व्यवस्था की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। महज 16 दिनों के भीतर पांच हत्याएं यह संकेत दे रही हैं कि अपराधियों के हौसले किस स्तर तक पहुंच चुके हैं। शहर के बीचोंबीच गोलियां चल रही हैं, गला रेतकर हत्या हो रही है और वारदात के बाद हमलावर आसानी से निकल जा रहे हैं। 29 जनवरी को विकासनगर में 18 वर्षीय छात्रा की हत्या से शुरू हुआ यह सिलसिला 31 जनवरी को ऋषिकेश में घर में घुसकर गोली मारने की घटना, 2 फरवरी को पलटन बाजार में दिनदहाड़े युवती की निर्मम हत्या, 11 फरवरी को तिब्बती मार्केट में 40 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या और 13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल के पास सरेआम फायरिंग तक जा पहुंचा। राजधानी के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में इस तरह की घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर सुरक्षा तंत्र की पकड़ कहां ढीली पड़ रही है। सबसे गंभीर प्रश्न पुलिस की सतर्कता और गश्त व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं। क्या खुफिया इनपुट विफल हो रहे हैं? क्या अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है? जब बाजारों में दिनदहाड़े हत्या हो और हमलावर खुलेआम चुनौती देकर निकल जाएं, तो यह केवल एक आपराधिक वारदात नहीं रहती, बल्कि यह कानून के इकबाल पर सीधा प्रहार बन जाती है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने धामी सरकार की साख पर भी असर डाला है। विपक्ष हमलावर है, व्यापारिक वर्ग बेचैन है और आम लोग सुरक्षा को लेकर असमंजस में हैं। देहरादून आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां निर्णायक और कठोर कार्रवाई की अपेक्षा बढ़ गई है। 16 दिनों में पांच हत्याएं केवल आंकड़ा नहीं हैं, यह चेतावनी है कि यदि अपराध पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया गया तो राजधानी की पहचान और सरकार की विश्वसनीयता, दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है।

अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब कोई भी व्यक्ति राजधानी देहरादून में आता था तब वह अपने घरवालों और सगे संबंधियों को बताया करता था कि 'मैं दून में हूं और सुकून में हूं।' यह सच है कि देहरादून सुकून के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है।

लेकिन हाल के वर्षों में राजधानी देहरादून के बिगड़ते हालात भयावह संदेश दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वह शहर जिसे कभी शांत, सुरक्षित और सुसंस्कृत कहा जाता था, आज अपराधियों की शरणस्थली, सरेबाजार गोलियों की तड़तड़ाहट, दिनदहाड़े मर्डर होना अब आम बात होती जा रही है। राजधानी देहरादून में अब लोगों को डर लगने लगा है, पता नहीं कब, कहां से गोली चल जाए। राजधानी देहरादून में क्या आम और क्या खास सभी डर के साए में है। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। देवभूमि की

राजधानी देहरादून आज एक भारी, चुभते हुए सन्नाटे में खड़ी है। यह सामान्य खामोशी नहीं है। यह उन गोलियों की गूंज के बाद पसरा हुआ विराम है, जो भीड़भाड़ वाले बाजारों में चलीं। यह उन अचानक थम गई आवाजों की खामोशी है, जो दिनदहाड़े अफरा-तफरी में बदल गई। और सबसे बढ़कर, यह उस भरोसे में आई दरार की आहट है, जो जनता ने कानून और व्यवस्था पर वर्षों से टिका रखी थी। महज 16 दिनों के भीतर पांच हत्याएं। पांच जिंदगियां, पांच परिवार, पांच अलग-अलग घटनास्थल। लेकिन एक ही सवाल। क्या देहरादून में 'रूल ऑफ लॉ' वास्तव में ढेर हो चुका है? 29 जनवरी को विकासनगर में 18 वर्षीय छात्रा मनीषा तोमर की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। बारहवीं कक्षा की छात्रा, जिसे उसका ही चचेरा भाई दवा दिलाने के बहाने घर से ले गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह केवल एक जघन्य अपराध नहीं था, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक विश्वास पर भी चोट थी। उस दिन लोगों ने इसे एक अलग-थलग घटना मान लिया। लेकिन यह तो आने वाले भयावह सिलसिले की शुरुआत भर थी। 31 जनवरी को ऋषिकेश में एक महिला की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। निजी संबंधों के विवाद से जुड़ा यह मामला भी कानून-व्यवस्था की दृष्टि से कम गंभीर नहीं था। सवाल उठा-घर के भीतर तक पहुंचकर हत्या करने का दुस्साहस आखिर अपराधियों को कहां से मिल रहा है? 2 फरवरी को देहरादून के दिल पलटन बाजार में 23 वर्षीय युवती गुंजन की गला रेतकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। यह घटना केवल एक अपराध नहीं थी, यह राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुली चुनौती थी। भीड़भाड़ वाले बाजार में, जहां सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं, वहां इस तरह की निर्मम हत्या ने व्यापारियों और आम नागरिकों को झकझोर दिया। बाजार बंद हुए, विरोध हुआ, और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठे। 11 फरवरी को तिब्बती मार्केट में 40 वर्षीय अर्जुन शर्मा को गोली मार दी गई। बाजार क्षेत्र, आम आवाजाही, और उसके बीच गोलियां चलना, यह किसी फिल्मी दृश्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यह देहरादून की हकीकत थी। अपराधी आए, गोली चलाई और निकल गए। क्या उन्हें पकड़ने का भय नहीं था? क्या निगरानी तंत्र इतना कमजोर पड़ चुका है? और फिर 13 फरवरी को देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल के पास कुख्यात विक्रम शर्मा की सरेआम गोली मारकर हत्या। यह घटना अपराध की दुनिया से जुड़े व्यक्ति की थी, लेकिन स्थान और तरीका फिर वही खुलेआम फायरिंग। यह

धामी सरकार का बड़ा एक्शन, देहरादून सहित कई जिलों के एसएसपी बदले

देहरादून की सड़कों पर बीते दिनों बहा खून सिर्फ अपराध की वारदात नहीं था, वह कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल भी था। सोलह दिनों के भीतर पांच हत्याओं ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया। जनता के मन में उठते सवालों और बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने आखिरकार सख्त संदेश देने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को सत्ता के गलियारों से जो आदेश निकला, उसने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। यह सिर्फ तबादला सूची नहीं थी, बल्कि साफ संकेत था कि लापरवाही या ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक झटके में कई अहम जिलों की कमान बदल दी। राजधानी देहरादून से लेकर कुमाऊं और गढ़वाल के जिलों तक पुलिस नेतृत्व में व्यापक फेरबदल कर दिया गया। सबसे बड़ा फैसला देहरादून के एसएसपी को हटाने का रहा, जो हालिया घटनाओं के बाद चर्चा के केंद्र में थे। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून-व्यवस्था से जुड़ा कोई भी संकेत हल्के में नहीं लिया जाएगा। पुलिस महकमे के भीतर भी यह संदेश गया है कि परिणाम आधारित काम ही अब पैमाना होगा। राजधानी की कमान बदली, तो हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे संवेदनशील जिलों में भी नए चेहरे तैनात कर दिए गए। एसटीएफ, अभिसूचना, एसडीआरएफ और पीएसी तक में जिम्मेदारियां पुनर्गठित की गई। यह फेरबदल प्रशासनिक औपचारिकता से कहीं ज्यादा, रणनीतिक पुनर्सरचना के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की मंशा साफ है, अपराध पर नकेल, व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही तय। देहरादून में हालिया घटनाओं के बाद एसएसपी अजय सिंह को हटाकर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय सिंह पहले भी एसटीएफ की कमान संभाल चुके हैं। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल को देहरादून का नया एसएसपी बनाया गया है। वहीं, अब तक एसटीएफ एसएसपी रहे नवनीत सिंह भुल्लर को हरिद्वार का कप्तान नियुक्त किया गया है। एसडीआरएफ की डीआईजी निवेदिता कुकरेती को आईजी एसडीआरएफ बनाया गया है। एसपी सतर्कता मुख्यालय प्रहलाद नारायण मीणा को पुलिस उपमहानिरीक्षक सतर्कता मुख्यालय के पद पर तैनाती दी गई है। 31वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक यशवंत सिंह को पीटीसी नरेंद्र नगर का प्रधानाचार्य बनाया गया है। एसपी चंपावत अजय गणपति कुमार को ऊधमसिंह नगर का एसपी बनाया गया है। ऊधमसिंह नगर के कप्तान मणिकांत मिश्र को एसपी अभिसूचना नियुक्त किया गया है, जबकि एसपी अभिसूचना प्रदीप कुमार राय को सीबीसीआईडी का एसपी बनाया गया है। अभिसूचना में एसपी (क्षेत्रीय) की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित श्रीवास्तव को सेनानायक आईआरबी प्रथम रामनगर भेजा गया है। एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे को पिथौरागढ़ का एसपी नियुक्त किया गया है। पिथौरागढ़ की एसपी रेखा यादव को चंपावत का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बागेश्वर के पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर. घोड़के को अल्मोड़ा का एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि अल्मोड़ा के एसपी देवेंद्र पिंचा को 31वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर का सेनानायक बनाया गया है। एसपी अपराध एवं यातायात ऊधमसिंह नगर निहारिका तोमर को रुद्रप्रयाग का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। एसपी अपराध एवं यातायात हरिद्वार जितेंद्र कुमार मेहरा को एसपी बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है। हरिद्वार एसपी जितेंद्र चौधरी को अपराध एवं यातायात ऊधमसिंह नगर का एसपी बनाया गया है। हरिद्वार एसपी निशा यादव को पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात हरिद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एएसपी सीआईडी मनोज ठाकुर को एसपी कोटद्वार नियुक्त किया गया है। एसपी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल चंद्र सिंह को पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य में हुए इस व्यापक फेरबदल को कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नए नियुक्त अधिकारी अपने-अपने जिलों में किस तरह से अपराध पर नियंत्रण और पुलिसिंग की साख को मजबूत करते हैं।

संदेश साफ था कि अपराधी अब छिपकर नहीं, बल्कि सामने आकर वारदात कर रहे हैं। इन पांच घटनाओं को यदि अलग-अलग देखें तो हर मामले की अपनी पृष्ठभूमि है। लेकिन यदि इन्हें एक क्रम में जोड़ें तो तस्वीर बेहद चिंताजनक नजर आती है। राजधानी के अलग-अलग हिस्सों, विकासनगर, ऋषिकेश, पलटन बाजार, तिब्बती मार्केट, सिल्वर सिटी मॉल में हुई हत्याएं बताती हैं कि अपराध किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। सबसे बड़ा प्रश्न पुलिस की भूमिका पर उठ रहा है। क्या गश्त व्यवस्था प्रभावी है? क्या खुफिया इनपुट समय पर मिल रहे हैं? क्या संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी पर्याप्त है? जब बाजारों में, मॉल के पास और घरों के भीतर तक अपराधी पहुंच जा रहे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। यह सुरक्षा तंत्र की कमजोरी की ओर इशारा करता है। राजधानी में कानून का इकबाल तभी कायम रहता है जब अपराधी वारदात से पहले डरें। लेकिन यहां तस्वीर उलट दिखाई दे रही है। अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता नजर आ रहा है। वारदात के बाद उनका तेजी से फरार हो जाना पुलिस की प्रतिक्रिया समय और रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। इन घटनाओं का राजनीतिक असर भी कम नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के दावे करती रही है। लेकिन राजधानी में 16 दिनों में पांच हत्याएं उन दावों की कसौटी बन गई हैं। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता करार दिया है, जबकि आम जनता के बीच भी चर्चा है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन-सी चूक है, जो लगातार सामने आ रही है। देहरादून की पहचान लंबे समय तक एक शैक्षणिक और शांत शहर की रही है। यहां देशभर से छात्र पढ़ने आते हैं, परिवार सुरक्षित भविष्य की उम्मीद लेकर बसते हैं। लेकिन हालिया घटनाओं ने उस छवि को धूमिल किया है। व्यापारिक संगठनों की नाराजगी, बाजार बंद करने के निर्णय और नागरिकों की बेचैनी संकेत दे रही है कि भरोसा कमजोर हो रहा है। कानून-व्यवस्था केवल अपराध दर्ज करने और आरोपियों को पकड़ने तक सीमित नहीं होती। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है, एक ऐसा भरोसा कि राज्य आपके साथ खड़ा है और अपराधी कानून से बच नहीं सकते। जब कम समय में बार-बार हत्याएं होती हैं, तो यह भरोसा दरकने लगता है। अब चुनौती केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। चुनौती है उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की, जिससे अपराधी वारदात से पहले सौ बार सोचें। चुनौती है पुलिस तंत्र को सक्रिय, सतर्क और प्रभावी बनाने की। और चुनौती है सरकार के लिए अपनी साख को बचाने की, क्योंकि राजधानी की कानून-व्यवस्था पूरे प्रदेश की छवि तय करती है। 16 दिनों में पांच हत्याएं, यह आंकड़ा मात्र संख्या नहीं है। यह एक चेतावनी है। यदि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, यदि पुलिस व्यवस्था में तत्काल सुधार और कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो देहरादून की पहचान पर लगा यह दाग और गहरा हो सकता है। राजधानी देहरादून आज एक निर्णायक मोड़ पर है। यहां से या तो कानून का इकबाल फिर से स्थापित होगा, या फिर अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। आने वाले दिन तय करेंगे कि देहरादून अपनी पुरानी साख लौटाता है या 'रूल ऑफ लॉ' की बहाली के लिए और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल, सरकार तुरंत करे उच्चस्तरीय समीक्षाः यशपाल आर्य

राजधानी देहरादून में लगातार हो रही हत्याओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। विगत 14 दिनों के भीतर पांच हत्याओं की घटनाओं को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न है। यशपाल आर्य ने कहा कि जब प्रदेश की राजधानी ही असुरक्षित नजर आए, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? उनके अनुसार राज्य में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और शासन-प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ प्रतीत होता है। आर्य ने कहा कि हत्या जैसी जघन्य घटनाओं का लगातार सामने आना कई गंभीर संकेत देता है। उनके मुताबिक या तो पुलिस तंत्र पर अत्यधिक दबाव है या कार्यप्रणाली में ढिलाई है। साथ ही अपराधियों में कानून का भय कम होता दिखाई दे रहा है और खुफिया तथा निगरानी व्यवस्था भी कमजोर पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राजधानी में 15 दिन में 5 हत्याएं होना किसी भी सरकार के लिए चेतावनी है। यह केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि हर परिवार की सुरक्षा और विश्वास से जुड़ा सवाल है।

अर्जुन हत्याकांड का खुलासा, 12 लाख की सुपारी, सगे भाई शूटर, मां बीना शर्मा समेत पांच गिरफ्तार

देहरादून की तिब्बती मार्केट में 11 फरवरी की सुबह हुई अर्जुन शर्मा की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश संपत्ति विवाद को लेकर रची गई थी और 12 लाख रुपये में सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया गया। घटना को अंजाम देने वाले दोनों शूटर सगे भाई हैं, जबकि साजिश में मृतक की मां बीना शर्मा समेत कुल पांच लोगों की भूमिका पाई गई है। पुलिस मुठभेड़ में घायल दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य तीन आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 11 फरवरी को सुबह करीब 10:30 बजे कोतवाली डालनवाला पुलिस को सूचना मिली कि तिब्बती मार्केट के पास स्कूटी सवार दो बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को दून अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान इंदिरा नगर निवासी अर्जुन शर्मा के रूप में हुई, जो जीएमएस रोड स्थित अमरदीप गैस एजेंसी के स्वामी थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर अलग-अलग टीमें गठित की गई। शहर और देहात क्षेत्रों में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दो स्कूटी सवार हमलावरों की पहचान सामने आई। चेकिंग के दौरान 11-12 फरवरी की रात रायपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर इलाके में एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पर फायरिंग कर जंगल की ओर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुआ। उसने अपना नाम राजीव उर्फ राजू बताया। इसी रात डोईवाला के लालतप्पड़ क्षेत्र में बैरियर पर एक अन्य स्कूटी सवार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और

बिरला फैक्ट्री परिसर में घुसकर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह भी पैर में गोली लगने से घायल हुआ। उसकी पहचान पंकज राणा के रूप में हुई। दोनों ने पूछताछ में अर्जुन शर्मा की हत्या स्वीकार की। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और मूल रूप से ग्राम देवीखाल, गुमखाल, कोटद्वार (जिला पौड़ी गढ़वाल) के निवासी हैं। वर्तमान में वे चक्खुवाला, देहरादून में रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से दो तमंचे 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में अलग से मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

संपत्ति विवाद बना अर्जुन शर्मा की हत्या की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि अर्जुन शर्मा का अपनी मां बीना शर्मा और उनके सहयोगियों के साथ संपत्ति और पैसों के लेन-देन को लेकर गंभीर विवाद चल रहा था। जीएमएस रोड स्थित एक संपत्ति की करीब 14 करोड़ रुपये में डील डॉ. अजय खन्ना के साथ हुई थी, जिसमें से लगभग 8 करोड़ रुपये बीना शर्मा को दिए जा चुके थे। लेकिन अर्जुन शर्मा ने उक्त संपत्ति के विक्रय पर न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया था, जिसके चलते डील अटक गई थी। इसी विवाद को लेकर मां-बेटे के बीच तनाव बढ़ गया था। जांच में यह भी सामने आया कि बीना शर्मा ने घटना से कुछ दिन पहले अर्जुन की दिनचर्या के बारे में जानकारी जुटवाई थी। पुलिस के अनुसार, डॉ. अजय खन्ना, विनोद उनियाल और बीना शर्मा ने मिलकर अर्जुन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और 12 लाख रुपये में सुपारी तय की गई। तीन लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे, शेष रकम वारदात के बाद दी जानी थी। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि वारदात से पहले और बाद में पंकज राणा की व्हाट्सएप के माध्यम से विनोद उनियाल से बातचीत हुई थी और घटना के बाद वह उसके घर भी गया था। साजिश में शामिल पाए जाने पर पुलिस ने बीना शर्मा, विनोद उनियाल और डॉ. अजय खन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। मुख्य शूटर पंकज राणा और राजीव उर्फ राजू को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने 2 तमंचे जिंदा और खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की है।

देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में दिनदहाड़े कुख्यात विक्रम शर्मा की हत्या

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बार फिर गोलियों की आवाज से दहल उठी। शहर के व्यस्त सिल्वर सिटी मॉल में शुक्रवार सुबह हुए सनसनीखेज शूटआउट ने न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि यह भी उजागर कर दिया कि बाहरी राज्यों के कुख्यात अपराधी किस तरह दून में गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं। मृतक की पहचान झारखंड के जमशेदपुर निवासी विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जो आपराधिक जगत का बड़ा नाम माना जाता था। वह झारखंड की दुमका जेल में बंद कुख्यात माफिया डॉन अखिलेश सिंह का आपराधिक गुरु बताया जाता है। पुलिस के अनुसार घटना सुबह करीब 10 बजे की है। विक्रम शर्मा सिल्वर सिटी मॉल स्थित जिम से वर्कआउट कर बाहर निकल रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए दो हमलावर पैदल पहुंचे और नजदीक से पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तीन गोलियां लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। मॉल परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि विक्रम शर्मा पिछले करीब दस वर्षों से देहरादून की एक पॉश कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहा था। स्थानीय स्तर पर उसकी पहचान एक कारोबारी, खासकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के रूप में थी। उसके आपराधिक अतीत की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। बताया जाता है कि उसके पिता टाटा स्टील में नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद देहरादून में बस गए थे। विक्रम का छोटा भाई अरविंद भी दून में ही रहता है।

विक्रम शर्मा का लंबा आपराधिक इतिहास

विक्रम शर्मा पर झारखंड के जमशेदपुर में 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं। हालांकि कई मामलों में वह बरी भी हो चुका था। वर्ष 2017 में जमशेदपुर पुलिस ने उसे देहरादून से गिरफ्तार किया था। वह 2017 से 2021 तक जेल में रहा और 30 जनवरी 2021 को रांची के होटवार जेल से सशर्त जमानत पर रिहा हुआ। 2008 में टाटा स्टील के सिक्योरिटी हेड जयराम सिंह की हत्या, श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड, साकची के काशीडीह निवासी रवि चौरसिया पर फायरिंग, बर्मामाइंस में फायरिंग और परमजीत सिंह हत्याकांड समेत कई संगीन मामलों में उसका नाम सामने आया था। यह पहला मामला नहीं है जब किसी बाहरी राज्य के कुख्यात अपराधी की मौजूदगी दून में सामने आई हो। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड के कई हिस्ट्रीशीटर पूर्व में देहरादून में किराये के मकानों या होटलों में छिपे पाए गए हैं। प्रॉपर्टी निवेश, होटल व्यवसाय या छोटे कारोबार की आड़ में कई अपराधी यहां वर्षों तक टिके रहे। गैंगवार या ठेकेदारी विवाद के बाद भी कई बदमाश दून का रुख करते रहे हैं। विक्रम शर्मा हत्याकांड के बाद किरायेदार सत्यापन, होटल रिकॉर्ड और राज्यों के आपराधिक डाटाबेस के समन्वय को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या स्थानीय तंत्र को उनकी मौजूदगी की जानकारी नहीं होती, या फर्जी पहचान और शांत जीवनशैली की आड़ में वे आसानी से व्यवस्था को चकमा दे देते हैं? पुलिस का दावा और चुनौती देहरादून पुलिस का कहना है कि समय-समय पर बाहरी अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं और कई वांछित बदमाशों को गिरफ्तार कर संबंधित राज्यों को सौंपा गया है। लेकिन सिल्वर सिटी मॉल जैसी व्यस्त जगह पर दिनदहाड़े हुई यह हत्या संकेत दे रही है कि निगरानी तंत्र को और सशक्त करने की जरूरत है।

उत्तराखंड के सांसदों की निधि खर्च में सुस्ती

देवभूमि में विकास के नाम पर आवंटित करोड़ों रुपये या तो कागजों में उलझे हैं या फाइलों की धूल झाड़ने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के आठ सांसदों को उनके वर्तमान कार्यकाल में मिली 95.90 करोड़ रुपये की सांसद निधि में से दिसंबर 2025 तक महज 18 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है। हालात यह हैं कि सैकड़ों प्रस्तावित कार्यों में से 232 को स्वीकृति तक नहीं मिल सकी, जबकि स्वीकृत परियोजनाओं में भी 87 काम अब तक धरातल पर शुरू नहीं हो पाए हैं। सूचना के अधिकार के तहत सामने आए इस आंकड़े ने विकास की रफ्तार, प्रशासनिक कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं, तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सामुदायिक भवन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जरूरत बनी हुई है, दूसरी ओर उपलब्ध निधि का बड़ा हिस्सा उपयोग से बाहर है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर विकास की गाड़ी किस मोड़ पर अटक गई है?

जनता ने भरोसा देकर संसद भेजा, विकास के लिए करोड़ों रुपये आवंटित हुए, लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। उत्तराखंड के सांसदों को मिली सांसद निधि का बड़ा हिस्सा अब भी खर्च होने का इंतजार कर रहा है। गांवों में सड़कें अधूरी हैं, सामुदायिक भवनों के प्रस्ताव फाइलों में अटके हैं, पेयजल योजनाएं गति नहीं पकड़ पा रहीं, और कई विकास कार्य कागजों से बाहर ही नहीं आ सके। ऐसे में यह सवाल सीधे जनप्रतिनिधियों से है जब संसाधन उपलब्ध थे तो विकास की रफ्तार इतनी धीमी क्यों रही? सांसद निधि का उद्देश्य ही स्थानीय जरूरतों के अनुरूप त्वरित विकास कार्य कराना है, ताकि छोटी लेकिन महत्वपूर्ण परियोजनाएं बिना लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के पूरी हो सकें। मगर हालिया आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में यह मंशा अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुंच सकी। करोड़ों रुपये आवंटित होने के बावजूद बड़ी संख्या में कार्य स्वीकृति या क्रियान्वयन के स्तर पर अटके पड़े हैं। सूचना के अधिकार के तहत काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट को ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय, उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है। लोक सूचना अधिकारी, उपायुक्त प्रशासन हेमंती गुंजियाल ने पत्रांक 245531 के माध्यम से दिसंबर 2025 तक का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के कुल 8 सांसदों, 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा को कुल 95.90 करोड़ रुपये की सांसद निधि आवंटित हुई। इसमें 49 करोड़ रुपये लोकसभा सांसदों को तथा 46.90 करोड़ रुपये राज्यसभा सांसदों को मिले। लेकिन खर्च की स्थिति निराशाजनक रही। वर्तमान कार्यकाल में पूर्ण कार्यों पर कुल 7.08 करोड़ रुपये तथा चल रहे कार्यों पर 10.65 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यानी कुल मिलाकर केवल 18 प्रतिशत राशि ही उपयोग में लाई जा सकी। लोकसभा सांसदों की स्थिति और भी चिंताजनक है। पांचों लोकसभा सांसदों ने पूर्ण कार्यों पर 2.089 करोड़ रुपये तथा अपूर्ण/चल रहे कार्यों पर 1.191 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो कुल आवंटित राशि का लगभग 7 प्रतिशत है। इसके विपरीत राज्यसभा के तीन सांसदों ने पूर्ण कार्यों पर 4.99 करोड़ तथा चल रहे कार्यों पर 9.46 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो उनकी कुल निधि का लगभग 31 प्रतिशत है। यदि सांसदवार खर्च की बात करें तो नैनीताल-उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने 18 प्रतिशत निधि खर्च की है, जो लोकसभा सांसदों में सर्वाधिक है। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने 14 प्रतिशत निधि खर्च की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के मामले में दिसंबर 2025 तक खर्च शून्य दर्शाया गया है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा तथा हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 1 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च की है। राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल ने 47 प्रतिशत निधि खर्च कर सबसे आगे स्थान बनाया है। कल्पना सैनी ने 27 प्रतिशत तथा महेंद्र भट्ट ने 6 प्रतिशत निधि खर्च की है। कार्य प्रस्तावों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। कुल 232 प्रस्तावित कार्यों को अधिकारियों द्वारा स्वीकृति ही नहीं दी गई। वहीं स्वीकृत कार्यों में से 87 कार्य दिसंबर 2025 तक प्रारंभ नहीं हो सके। नैनीताल-उधमसिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने 316 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें से 229 स्वीकृत हुए। 54 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 154 कार्य प्रगति पर हैं तथा 21 कार्य प्रारंभ नहीं हुए। टिहरी गढ़वाल सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने 128 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें से 89 स्वीकृत हुए। 11 पूर्ण, 64 प्रगति पर तथा 14 कार्य प्रारंभ नहीं हुए। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने वर्तमान कार्यकाल में 4 कार्य प्रस्तावित किए। इनमें से 2 स्वीकृत हुए, 1 पूर्ण और 1 प्रगति पर है, लेकिन दिसंबर 2025 तक खर्च शून्य दर्शाया गया है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा के 4 स्वीकृत कार्यों में 2 प्रारंभ नहीं हुए तथा 2 प्रगति पर हैं। कुल खर्च 0.041 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जो 1 प्रतिशत से भी कम है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 16 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें से 10 स्वीकृत हुए। 1 पूर्ण, 5 प्रगति पर तथा 4 प्रारंभ नहीं हुए। कुल खर्च 0.080 करोड़ रुपये, यानी 1 प्रतिशत से कम है। राज्यसभा सांसदों में नरेश बंसल ने 191 कार्य प्रस्तावित किए, जिनमें से 144 स्वीकृत हुए। 23 पूर्ण, 92 प्रगति पर तथा 29 प्रारंभ नहीं हुए। कल्पना सैनी ने 121 कार्य प्रस्तावित किए, 89 स्वीकृत हुए। 26 पूर्ण, 60 प्रगति पर तथा 3 प्रारंभ नहीं हुए। महेंद्र भट्ट ने 44 कार्य प्रस्तावित किए, 23 स्वीकृत हुए। 2 पूर्ण, 7 प्रगति पर तथा 14 कार्य प्रारंभ नहीं हो सके। इन आंकड़ों ने प्रदेश में विकास की गति, प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता, तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सांसद निधि का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर त्वरित विकास सुनिश्चित करना है, लेकिन जब आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पा रहा, तो यह स्थिति चिंताजनक मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सांसद और संबंधित विभाग इस सुस्ती को दूर कर लंबित कार्यों को गति देंगे, या फिर करोड़ों रुपये यूं ही अधर में लटके रहेंगे।

दिलचस्प किस्से है प्रेम पत्रों के!

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

कुछ पत्र ऐसे प्रेम पत्र होते है, जो भुलाये नही भूलते, जिनमे लिखने वाले के प्यार की तस्वीर का अक्स नजर आने लगता है। ऐसे प्रेम पत्र उन लोगो द्वारा लिखे जाते रहे है जिनका दिल किसी ओर के लिए धकड़ रहा हो। इनमे अधिकांश तो जंवा ही होते है लेकिन उम्रदराज लोग भी प्रेम की पाती लिखने में पीछे नही रहे। हालांकि अब इसका रूप बदल गया है। बदलते जमाने के साथ प्रेम पत्रों का स्वरूप भी बदल गया है। अब सोशल मीडिया पर चौटिंग, वीडियो कॉलिंग आदि माध्यम से सहज प्रेम संवाद होने लगे है। लेकिन बीते जमाने मे कुछ ऐसे छुपे रूस्तम भी हुए है जिनके नाम जानकर आप सहज रूप में यकीन भी नही कर पाएगें कि ये छुपे रूस्तम प्रेम पत्र भी लिख सकते थे। हालांकि यह सच है कि कुछ ऐसे लोगो ने भी अपने प्रेम का इजहार अपनी प्रमिकाओं को प्रेम पत्र लिखकर किया है जो नामी गिरामी रहे है। यूं तो प्रेम के इजहार के तरीके सदियों से अलग अलग रहे है। पहले प्रेम पत्र के माध्यम से प्रेम का इजहार किया जाता था तो अब प्रेमपत्रों की जगह मोबाइल के एसएमएस, इन्टरनेट के फेसबुक, ई.मेल और चैटिंग ने ले ली है। लेकिन प्रेमी व प्रेमिका के बीच विरह वेदना के जो जज्बात प्रेम पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होते थे, उसकी पूर्ति हाइटेक प्रेम संवादो से नही हो सकती लैला, मजनू, शीरी.फरहाद जैसे अनेक प्रेमी युगल ऐसे पैदा हुए है, जिन्होने जमाने भर से लडकर अपने प्यार को विजय दिलाई थी। लेकिन समाज का एक बडा तबका ऐसा भी हुआ है जिनकी छवि तो एक प्रेमी या फिर प्रेमिका की नही थी परन्तु उन्होने जीवन के विभिन्न मोडो पर प्रेम पत्र लिखे है। जिन्हे देखकर आम आदमी भी रहत में पड़ जाता है और उसमें भी प्रेम के अंकुर प्रस्फूटित होने लगते है। वर्षो पहले नई दिल्ली के डांल्फिन बुक्स प्रकाशक ने दुनिया के नामी व्यक्तियो के प्रेत्रो को लेकर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक के लेखक वीरेन्द्र कुमार गुप्त ने दुनिया भर की बडी हस्तियो के जीवन में आए प्रेम के सुनहरे पलो को उनके प्रेम पत्रो के माध्यम से जो पता चला उसे आमजन के सामने लाने की कौशिश की है। 127 प्रेम पत्रो की इस पुस्तक रूपी गुलदस्ते में विदेशी हस्तियो के पत्र तो उन्हे आसानी से मिल गए थे। लेकिन भारतीय हस्तियों के प्रेम पत्र प्राप्त करने में उनहे खासी मशक्कत करनी पडी थी। क्योकि अधिकतर भारतीय नही चाहते थे कि उनके प्रेमपत्र सार्वजनिक हो। लेकिन वीरेन्द्र कुमार गुप्त ने हिम्मत करके भारत की कई हस्तियों के प्रेमपत्रों का खुलासा किया। इन प्रेमपत्रों में मुंशी प्रेमचन्द का शिवरानी को लिखा गया प्रेमपत्र जहां शामिल है। वहीं कवि नजरूल इस्लाम का अपनी पत्नी के नाम, स्वामी रामतीर्थ का अज्ञात के नाम, केएम मुंशी का अपनी पहली पत्नी के नाम, साहित्यकार मौलाना शिबली का अतिया फैजी के नाम, शायर इकबाल का अतिया के नाम, शायर दाग का मुन्नीबाई के नाम, अमर शहीद लुमुम्बा का अपनी पत्नी के नाम, महात्मा गांधी का अपनी पत्नी कस्तूबा के नाम, कवि नाजिम हिकमत का अपनी पत्नी के नाम व शायर हसरत मोहानी का अपनी पत्नी निशातुन्निसा बेगम के नाम लिखे गए प्रेमपत्र शामिल है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की बहन कृष्णा नेहरू का अपने भावी पति हथी सिंह को लिखा गया प्रेम पत्र, कवि गोपाल दास नीरज का एक अज्ञात महिला के नाम लिखा गया प्रेम पत्र, उपन्यासकार कृष्ण चन्द्र का किसी अज्ञात को लिखा गया प्रेमपत्र, कवियत्री अमृता प्रीतम, विष्णु प्रभाकर, सज्जाद जहीर व जानकी देवी बजाज के लिखे प्रेमपत्रों की रौचकता देखते ही बनती है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर डाले तो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहिम लिंकन, उपन्यासकार टाल्स्टाय, रानी विक्टोरिया, कवि ब्राउनिंग, मनोवैज्ञानिक डां फ्रायड, वैज्ञानिक लुईपास्चर, उधोगपति हेनरी फोर्ड, निबंधकार हैजलिट, विचारक रूसो, क्रांतिकारी मैजिनी, विजेता नेपोलियन, महारानी लूसी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, तानाशाह चार्ल्स प्रथम, संगीतज्ञ मोजार्ट, पर्यटक फ्रांसिस यंग, राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन, व्यंग्यकार बनार्ड शा, अणु वैज्ञानिक जूली रोजनबर्ग, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एन्टोनियटे, सेनापति रोमेल, अभिनेता स्टैनले, लेखिका वर्जीनिया ने भी अपने दिल की धडकनों को प्रेमपत्र लिखे थे जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बने है।पहले एक मात्र पत्र ही एक ऐसा माध्यम होता था, जो दूर बैठे प्रेमी या फिर प्रेमिका तक दिल की बात पहुंचाता था। ऐसे ही पत्रों को प्रेमपत्र का नाम दिया गया है। प्रेमपत्र हालांकि पूर्णत व्यक्तिगत और गोपनीय होता है। फिर भी देशऔर दुनिया के चर्चित व्यक्तियों के प्रेमपत्र सार्वजनिक करके वीरेंद्र कुमार गुप्त ने प्रेम की दुनिया की खिडकी खोलने का काम किया था। ताकि आने वाली पीढी इन प्रेमपत्रों से प्रेरित हो सके और प्रेमपत्रों का सिलसिला चलता रहे। जब तक जीवन है तब तक प्रेम है, इसलिए कभी प्यार और प्यार के इजहार से दूरी नही बनानी चाहिए। प्यार के लिए उम्र कोई मायने नही रखती। तभी तो बुजुर्ग लोग भी युवाओं की तरह ही अपने प्रेम का इजहार अपनी बुजुर्ग और कभी कभी अपनी उम्र से आधी यानि प्रेमिकाओं को करने से नही चूकते। किसी ने कहा भी है कि शरीर बुढा होता है, दिल नही। ऐसे में जब तक दिल धड़कता है तब तक प्रेम के इजहार की संभावना भी बनी रहती है। लेकिन प्रेम वासना रहित शुद्ध सात्विक हो तो वह ईश्वरीय प्रेम जैसा ही होता है। सच यह भी है कि अगर हम इतना प्रेम परमात्मा से करे तो जीवन सार्थक हो जाता है। (*लेखक विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति है)*

सगन्ध तेल विभिन्न रोगों के इलाज में हो सकते हैं उपयोगी
प्रमाणिक शोध की आवश्यकता- प्रो. मीनू सिंह

परफ्यूमरी एवं एरोमैटिक्स विषय पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन

सोमवार, 09 फरवरी 2025 सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तत्वाधान में परफ्यूमरी एवं एरोमैटिक्स विषय पर 05 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो. डॉ. मीनू सिंह, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), ऋषिकेश के द्वारा किया गया।

डॉ. नृपेन्द्र चौहान, निदेशक, कैप, सेलाकुई द्वारा मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों, प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत किया गया तथा उनके द्वारा कैप, सेलाकुई द्वारा की स्थापना एवं उसके उद्देश्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी तथा उत्तराखण्ड के लिये एरोमा सेक्टर की आवश्यकता एवं किये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। वर्तमान में कैप, सेलाकुई, कृषकों, शोधाथियों एवं उद्यमियों को कृषिकरण, प्रशिक्षण, गुणवत्तायुवत बीज-पौध, प्रसंस्करण, विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदि एक ही छत के नीचे सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रो. (डॉ.) मीनू सिंह. मुख्य अतिथि द्वारा अपने सम्बोधन में सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई द्वारा सगन्ध तेलों, एरोमा, परफ्यूमरी आदि क्षेत्रों में किये जा रहे शोध कार्यो की सराहना की। उनके द्वारा भविष्य में एरोमाथैरेपी के क्षेत्र में एम्स एवं कैप की मध्य संयुक्त रूप से शोध कार्य किये जाने पर जोर दिया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सगन्ध तेल विभिन्न रोगों के इलाज में उपयोगी हो सकते हैं। जिस हेतु प्रमाणीक शोध किये जाने की आवश्यकता है। जिसमें एम्स द्वारा कैप को शोध हेतु सहयोग किया जायेगा। मुख्य अतिथि द्वारा अपने सम्बोधन में सगन्ध उपचार की ध्यान (मेडिटेशन) में उपयोगिता के सम्बन्ध में अनुभव साझा किये गये। उद्घाटन सत्र से पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा कैप की दी स्टेट ऑफ दी आर्ट इत्र एवं परफ्यूमरी प्रयोगशाला का भ्रमण कर किये जा रहे शोध कार्यो की जानकारी प्राप्त की गयी।

डॉ. डेमा लोहनी, फाउन्डर निदेशक एवं वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा अपने सम्बोधन में बताया गया कि कैप में स्थापित इत्र एवं परफ्यूमरी प्रयोगशाला का लोकार्पण नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया है तथा राज्य स्थापना दिवस 09 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री अपने सम्बोधन में कहा गया कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखण्ड ने एरोमैटिक्स प्लान्ट के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। इसी परिकल्पना के क्रम में कैप, सेलाकुई द्वारा परफ्यूमरी एवं एरोमैटिक विषय पर चतुर्थ बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को यह भी सुझाव दिया कि प्रशिक्षण के उपरान्त एरोमा एवं परफ्यूमरी क्षेत्र में उद्दामिता एवं स्वरोजगार की असीम सम्भावना है। जिनका वह लाभ उठा सकते है।

कार्यक्रम में उपस्थित डॉ. कुवंर राज अस्थाना, सम्पादक, दिव्य हिमगिरि द्वारा अवगत कराया गया की उनका कैप के साथ कई वर्षो से जुड़ाव है तथा कैप द्वारा किये जा रहे शोध एवं विकास कार्यो का लाभ उत्तराखण्ड ही नहीं अपितु पूरे देश को मिल रहा है। उनके द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों से आये प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवश्य लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षक डॉ. प्रकाश नारायणन, मुख्य परफ्यूमर, जीवाडान, बैंगलौर द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को सगन्ध पौधा केन्द्र की सभी सुविधाओं को भरपूर लाभ लेने का सुझाव दिया गया। उनके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को यह भी विश्वास दिलाया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी भविष्य की योजनाओं के लिये अत्यन्त लाभकारी होगा।

कार्यक्रम में मुख्य ववत्ता के रूप में शवित विनय शुक्ला, निदेशक, एफ.एफ.डी.सी. कन्नौज, उ.प्र. द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया। उनके द्वारा सगन्ध तेलों एवं एरोमा के बाजार, आसवन एवं प्रसंस्करण हेतु तकनीकी जानकारी तथा सगन्ध क्षेत्र में विभिन्न स्वरोजगार के विकल्पों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। डॉ. गरिमा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. पंकज बिजल्वाण द्वारा किया गया तथा इस अवसर पर कैप के वैज्ञानिक डॉ. जफर हैदर, कु. जान्हवी, कु. प्रतीक्षा, रोहित आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के विजन में शहरी विकास को नई दिशा, हरिद्वार-रुड़की महायोजना 2041 पर राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

राज्य सरकार शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध- *डॉ. आर. राजेश कुमार*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर आज राज्य सचिवालय, देहरादून में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

भविष्य के शहरों का रोडमैप- बैठक में हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भूमि उपयोग, आवासीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास, यातायात प्रबंधन, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, पर्यावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। शशि मोहन श्रीवास्तव, चीफ टॉउन एंड कन्ट्री प्लॉनर ने इस योजना की बावत सभी महत्वपूर्ण जानकारी सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार से साझा की। शशि मोहन श्रीवास्तव द्वारा महायोजना के प्रारूप की विस्तृत प्रस्तुति देते हुए अब तक की गई कार्यवाही और आगामी चरणों की जानकारी दी गई।

सार्वजनिक सहभागिता को मिला विशेष महत्व- उल्लेखनीय है कि हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 के प्रारूप पर सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हरिद्वार महायोजना के लिए लगभग 350 तथा रुड़की महायोजना के लिए लगभग 550 सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। बैठक के दौरान इन सभी आपत्तियों एवं सुझावों पर बिंदुवार चर्चा करते हुए उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर मंथन किया गया। आवास सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रत्येक सुझाव का गंभीरता, पारदर्शिता एवं नियमानुसार परीक्षण किया जाए, ताकि महायोजना जनअपेक्षाओं के अनुरूप और व्यावहारिक बन सके।

नियोजित विकास से सशक्त होगा हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र- आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड के शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना-2041 का उद्देश्य केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण, बेहतर यातायात व्यवस्था, सुदृढ़ आधारभूत ढांचा और नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना भी शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है, ताकि महायोजना वास्तविक जरूरतों को प्रतिबिंबित कर सके। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए महायोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, जिससे क्षेत्र के नियोजित एवं सतत विकास को नई गति मिल सके।

शीघ्र अनुमोदन की दिशा में कार्रवाई- बैठक के अंत में आवास सचिव द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि महायोजना-2041 को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि इसे शीघ्र शासन स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि महायोजना का प्रभावी क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में हरिद्वार एवं रुड़की को आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

‘शी फॉर स्टेम’ कार्यशाला में सीएम धामी ने 20 छात्राओं को दी 50-50 हजार की छात्रवृत्ति

स्टेम हेतु स्टार्टअप आरंभ करने के लिए में छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे

बालिकाओं में विज्ञान एवं नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने के लिए स्टेम आधारित कार्यक्रमों का किया जा रहा विस्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला (प्रेमनगर, देहरादून) में आयोजित ‘शी फॉर स्टेम उत्तराखण्ड’ विषयक कार्यशाला में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस’ के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं तथा कार्यशाला में उपस्थित सभी महानुभावों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने ‘शी फॉर स्टेम’ विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम प्रदेश की 20 प्रतिभाशाली बेटियों को 50-50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि शी फॉर स्टेम के तहत हर जनपद में पांच छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि स्टेम हेतु स्टार्टअप आरंभ करने के लिए में छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। महिला प्रौद्योगिकी केंद्रों में स्वयं सहायता समूहो को जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से होनहार बेटियों को स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में शिक्षा एवं करियर के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए इन-मोबी, विज्ञानशाला इंटरनेशनल, यूकॉस्ट तथा उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित सभी आयोजकों को साधुवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इस दूरदर्शी पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय इतिहास साक्षी है कि नारीशक्ति केवल सामाजिक या पारिवारिक जीवन तक सीमित नहीं रही, बल्कि विज्ञान, दर्शन, खगोलशास्त्र एवं चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी रही है। वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ दार्शनिक विमर्श में अग्रणी थीं, जबकि लीलावती ने गणित के क्षेत्र में विश्व को दिशा प्रदान की। उन्होंने उल्लेख किया कि चरक-संहिता और सुश्रुत-संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों के विकास में भी स्त्रियों के योगदान के प्रमाण मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक काल में भी अनेक महिलाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान देकर देश का गौरव बढ़ाया है। स्वतंत्रता से पूर्व के समय में, जब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना भी चुनौतीपूर्ण था, अन्ना मणि ने भारत की पहली महिला मौसम वैज्ञानिक बनकर इतिहास रचा और ‘वेदर वुमन ऑफ इंडिया’ के रूप में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक उपकरणों के विकास में अमूल्य योगदान दिया। इसी प्रकार कमला सोहोनी विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला बनीं और यह सिद्ध किया कि प्रतिभा किसी बंधन की मोहताज नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान भारत में डॉ. टेसी थॉमस, जिन्हें ‘मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया’ कहा जाता है, ने अग्नि-4 और अग्नि-5 जैसी महत्वपूर्ण मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व कर देश की सामरिक शक्ति को नई ऊँचाइयाँ दी हैं। साथ ही ‘रॉकेट वुमन’ के नाम से प्रसिद्ध डॉ. ऋतु करिधल ने मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारत को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी महान विभूतियों का जीवन यह संदेश देता है कि जब नारी को अवसर मिलता है तो वह न केवल अपने लिए मार्ग बनाती है, बल्कि पूरे राष्ट्र को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। उन्होंने कहा कि यह संयोग नहीं है कि आज भारत में स्टेम क्षेत्रों से स्नातक होने वाले विद्यार्थियों में लगभग 42-43 प्रतिशत छात्राएँ हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में अधिक है। यह आँकड़ा इस बात का प्रमाण है कि भारत की बेटियाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित के क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं तथा नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। उन्होंने कहा कि

अब आवश्यकता इस बात की है कि बेटियों को अवसर, संसाधन और विश्वास देकर उनके सपनों को उड़ान दी जाए, ताकि वे अपने भविष्य के साथ-साथ विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करने में योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मत है कि इक्कीसवीं सदी में भारत की प्रगति विज्ञान और तकनीकी नवाचार पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊँचाइयाँ प्राप्त की हैं। कोरोना वैक्सीन निर्माण, चंद्रयान-3, आदित्य एल१ और गगनयान मिशन जैसी उपलब्धियों ने देश को नए कीर्तिमान स्थापित करने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी आधी आबादी तकनीकी रूप से कितनी सक्षम है और नवाचार के क्षेत्र में कितना योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दृष्टिकोण के साथ महिलाओं और बेटियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से महिलाओं की डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है। स्टेम शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को प्रेरित किया जा रहा है, जबकि प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इंस्पायर योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्राओं को विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए सहायता दी जा रही है। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स में बालिकाओं को रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। महिला वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत महिलाओं को अनुसंधान हेतु फैलोशिप प्रदान की जा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भी महिलाओं एवं बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा स्टेम में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राज्य सरकार भी उत्तराखंड में विज्ञान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है। राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की गई है तथा टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप सुदृढ़ इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। राज्य में साइंस एवं इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट सूचना केंद्र और स्टेम लैब्स के माध्यम से विश्वस्तरीय अवसंरचना तैयार की जा रही है। एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री-इनक्यूबेशन लैब की स्थापना को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो शीघ्र पूर्ण होकर राज्य को विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह साइंस सिटी उत्तराखंड को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बेटियाँ बिना किसी बाधा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और देश-प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 में बाबा केदार की पावन भूमि से प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त कथन- "21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा", का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार 'विकल्प रहित संकल्प' के साथ इसे साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प तभी सिद्ध होगा जब उत्तराखंड की प्रत्येक बेटी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनकर प्रदेश के समग्र विकास में समान रूप से सहभागी बनेगी। मुख्यमंत्री ने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया कि 'शी फॉर स्टेम' जैसे प्रयास प्रदेश की बेटियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे तथा वे अपने ज्ञान, कौशल और समर्पण से देश और प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। कार्यक्रम में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, सचिव रंजीत सिन्हा, महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो. दुर्गेश पंत सहित छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

डीडीए प्रथम पग फाउंडेशन कोर्स-2 के कैडेट्स ने पीओपी में दिखाया दमखम

- युवाओं को मोटिवेट करने के उद्देश्य से एनडीए की तर्ज पर आयोजित की गई पासिंग आउट परेड
- 12 गर्ल्स समेत कुल 106 कैडेट्स ने की कदमताल, अंतिम पग पार करने के बाद दोहराया संकल्प

सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा का सपना देखने वाले दून डिफेंस एकेडमी के होनहार युवाओं के लिए शनिवार का दिन यादगार रहा। एकेडमी में एनडीए की तर्ज पर पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 12 गर्ल्स समेत कुल 106 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। अंतिम पग पार करने के बाद उन्होंने मेहनत व अनुशासन के साथ देश सेवा करने का अपना संकल्प दोहराया।

सहस्त्रधारा रोड स्थित एकेडमी के त्रिशक्ति कैंपस में शनिवार को प्रथम पग, फाउंडेशन कोर्स-2 के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। डिफेंस कोचिंग कर रहे यह सभी युवा अब 12वीं की परीक्षा देंगे। जल, वायु, थल और अग्नि हाउस के बैनर तले उन्होंने ड्रिल स्क्वायर पर शानदार परेड की। बतौर मुख्य अतिथि ले.ज. गंभीर सिंह नेगी (सेनि) ने परेड की सलामी ली।

रिव्यूइंग ऑफिसर ले.ज. गंभीर सिंह नेगी (सेनि) ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस परेड ग्राउंड पर आपके कदमों की गूंज केवल अभ्यास की नहीं, बल्कि आपके संकल्प की आवाज है। इस समय की पढ़ाई, मेहनत, अभ्यास और अनुशासन आपके सुरक्षित व सफल भविष्य की गारंटी बनेगा। सेना की परंपरा हमें सिखाती है कि वर्दी पहनना गर्व है, और उसे निभाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी। आज आप साबित कर चुके हैं कि अनुशासन, मेहनत और टीम भावना क्या होती है। दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि एनडीए की तर्ज पर इस परेड को आयोजित करने का उद्देश्य कैडेट्स को मोटिवेट करना है। उन्होंने बताया कि कोर्स वन के कई कैडेट्स एनडीए व नेवी ज्वाइन कर चुके हैं। अब कोर्स फोर के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही, एकेडमी ने कक्षा छह से 12 तक के लिए इंटिग्रेटेड रेजिडेंशियल प्रोग्राम की भी शुरूआत की है, जिसके तहत स्कूलिंग के साथ-साथ एनडीए, मर्चेंट नेवी, सीपीएल, जेईई और क्रिकेट की कोचिंग करवाई जाएगी। इस अवसर पर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के पूर्व प्रिंसिपल ब्रिगेडियर विनोद पसबोला (सेनि), डीडीए की डिप्टी डायरेक्टर दिव्या असवाल गुप्ता, एकलव्य गुप्ता समेत एकेडमी की सभी फैकल्टी व स्टाफ मौजूद रहा।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारंभ

राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को मिलेगी नई दिशा

मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को भेजी 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ करते हुए प्रथम चरण में जनपद बागेश्वर (42 लाभार्थी) , देहरादून (191), नैनीताल (75), पौड़ी (66), टिहरी (23) एवं उध्ज्ञमसिंहनगर (97) के कुल 494 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में रू. 3 करोड़ 45 लाख 34,500 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विभागीय कैलेंडर का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा राज्य की लाखों महिलाओं के संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास को नई दिशा दी जा रही है। महिलाओं के बिना किसी भी राष्ट्र और समाज की उन्नति संभव नहीं है। महिला के सशक्त होने से परिवार के साथ पूरा समाज सशक्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना में हमने विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी भी कारण से अकेले जीवन का भार उठाने वाली महिलाओं के साथ एसिड अटैक, आपराधिक घटना की पीड़िता, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा इस योजना के शुरू होने से राज्य की नारी शक्ति अब नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए निरन्तर कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं अभियान, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना के साथ ही ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, राज्य की मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर प्रदान किए जा रहें हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में लगभग 5 लाख महिलाएँ 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। 7 हजार से अधिक ग्राम्य संगठन और 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएँ सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल भी पेश कर रही हैं। प्रदेश की 1 लाख 69 हजार से अधिक बहनों ने लखपति दीदी' बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने का काम किया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी किया है।

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अब महिलाओं को किसी और के ऊपर निर्भर न रखकर खुद आत्मनिर्भर बनेंगी साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ेगी। उन्होंने कहा निश्चित ही यह योजना एकल महिलाओं की तस्वीर बदलने का काम करेंगी।

सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना एक सशक्त महिला उद्यमी योजना है। उन्होंने बताया योजना के अंतर्गत अधिकतम धनराशि 2 लाख तक के कार्य/परियोजना स्वीकृत किए जा रहे हैं। लाभार्थी द्वारा स्वयं के श्रोतों/लोन के रूप में ली गयी धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत अथवा 1.50 लाख (जो भी अधिकतम हो) धनराशि की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया योजना के अंतर्गत परियोजना हेतु महिला को विभागीय अनुदान धनराशि 75% देय होगी एवं महिला का स्वयं का अंशदान 25% अनिवार्य रूप से देय होगा।

इस अवसर पर डायरेक्टर बी एल राणा, विक्रम, आरती, मोहित चौधरी एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

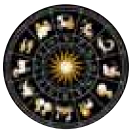
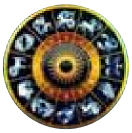
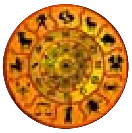

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- किसी भी असमंजस में अनुभवी और वरिष्ठ लोगों की सलाह जरूर लें, इससे बेहतर नतीजे मिलेंगे। पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी और फिलहाल उन पर पूरी कटौती कर पाना मुश्किल रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी न दें, वरना धोखा मिल सकता है। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

वृषभ राशि- विद्यार्थी पढ़ाई पर अच्छा फोकस रखेंगे। व्यवसाय की वर्तमान कार्यप्रणाली में अभी बड़ा बदलाव न करें। मार्केटिंग और पेमेंट कलेक्शन के लिए समय अनुकूल है। लापरवाही के कारण कोई डील रद्द भी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों पर कार्यभार बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 9

मिथुन राशि- नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य न खोएं, विनम्रता से बात करने पर विवाद आसानी से सुलझेंगे। पारिवारिक संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप से खटास आ सकती है, इसलिए विवेक से काम लें। बच्चों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं। परिवार की नाराजगी को समय रहते दूर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

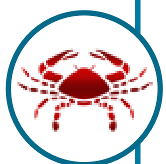

कर्क राशि- कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। घर में किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी प्रस्ताव आने की संभावना है। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानजनक रहेगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 6

सिंह राशि- युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, सीखने का अवसर भी मिलेगा। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखने के लिए प्रयास करना होगा। संतान की किसी गतिविधि से चिंता बढ़ सकती है। निवेश से जुड़े फैसलों में जरूरत हो तो समय पर निर्णय लें। संतुलित खानपान और नियमित दिनचर्या रखें। भाग्यशाली रंग- गहरा लाल, भाग्यशाली अंक- 3

कन्या राशि- दिन बेहतर बनाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। बातचीत और निर्णय में दिल की बजाय दिमाग का संतुलित उपयोग लाभ देगा। विवादित मामले में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। दांपत्य संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 8

तुला राशि- बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जांच करें। फिलहाल नया बड़ा निर्णय टालना बेहतर रहेगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से स्थिति संभल जाएगी। किसी योजना को लागू करने से पहले पूरी जानकारी लें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 2

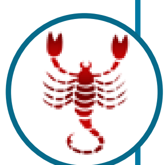

वृश्चिक राशि- समय अनुकूल है। लंबे समय से चली आ रही चिंता में राहत मिलेगी और आप अपने निजी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। संपत्ति संबंधी विवाद में घर के वरिष्ठ सदस्य की सलाह समाधान दे सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। आपसी संबंध मधुर बने रहेंगे। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 5

धनु राशि- अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करें, सफलता के योग मजबूत हैं। मनपसंद गतिविधियों में निवेश से प्रसन्नता रहेगी। पड़ोसियों से मतभेद दूर होंगे। आपका सकारात्मक स्वभाव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। कार्यक्षेत्र में धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मौसम को हल्के में न लें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 4

मकर राशि- अनावश्यक कामों में समय अधिक निकल जाएगा, जिससे परिवार को समय देना कठिन होगा। किसी नजदीकी मित्र को पैसा उधार देना पड़ सकता है। घर और काम दोनों जगह तालमेल बना रहेगा। परिवार में शांति रहेगी। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पर्याप्त आराम लेना जरूरी है। भाग्यशाली रंग- गहरा पीला, भाग्यशाली अंक- 1

कुंभ राशि- प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होकर उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कार्यक्षमता निखरेगी। किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। प्राथमिकता वाले कामों की सूची स्पष्ट रखें। अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार न लें। दिखावे के कारण अतिरिक्त खर्च या कर्ज लेने से बचें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 7

मीन राशि- अधिक सफलता पाने के लिए गलत रास्ता न चुनें। अवांछित लोगों से दूरी बनाए रखें। प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। पार्टनरशिप वाले काम में लाभ की स्थिति बन रही है। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा और ओवरटाइम करना पड़ सकता है। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 4